

सत्य बोलकर मित्र बनाना अच्छा है, परन्तु झूठ बोलकर मित्र बनाने से सत्य बोलकर शत्रु बनाना अधिक अच्छा है, क्योंकि आप संसार में सबको एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकते।

03 गर्मी से राहत की नई पहल: कश्मीरी गेट ISBT पर लगी पहली स्मार्ट वॉटर डिस्पेंसिंग मशीन

06 पत्रकारिता: चुनौती एवं भविष्य

08 "नेताओं की देशभक्ति की अनिपरीक्षा, सेना में बेटा भेजो, पेंशन लो!"

---चार दिन शेष--- सम्मान प्राप्त करने के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि 4 मई 2025

परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अपनी योग्यता/ कार्यशैली / जनहित में समर्पण के आधार पर सम्मान प्राप्त करने के लिए आनलाइन गूगल फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि है 4 मई 2025, इसके बाद फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह सम्मान सिर्फ आपकी योग्यता के आधार पर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। सम्मान प्राप्त करने के लिए फार्म निशुल्क है और सम्मान भी योग्यता के आधार पर है जिसका कोई शुल्क/ चार्ज नहीं है। 12 तारीख तक फार्म की जांच के उपरान्त सफल मान्यगणों को मेल/ व्हाट्सएप द्वारा सूचित किया जाएगा और साथ ही समारोह में उपस्थित होने के लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त जारी किया जाएगा। 17 मई दिन शनिवार को कंस्टीट्यूशन क्लब आफ इंडिया में 3 pm से 6 pm तक सम्मान वितरण किया जाएगा। इस समारोह में प्रवेश सिर्फ निमंत्रित अतिथियों को निमंत्रण पत्र के आधार पर ही मिलेगा। आम व्यक्तियों के लिए सम्मान समारोह हाल में प्रवेश वर्जित है अतः आने से पूर्व अपने निमंत्रण पत्र की जांच अवश्य

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

द्वितीय वार्षिक सम्मान समारोह

दिनांक : शनिवार 17 मई 2025. प्रातः 10:00 से 7 बजे तक
स्थान : स्पीकर हॉल, कॉन्वेंट्सूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली

:- मुख्य अतिथि:-
श्री शंभू सिंह, आईएसएस
सचिव शिपिंग भारत सरकार (सेवानिवृत्त) शिपिंग मंत्रालय

:- विशेषज्ञ वक्ता:-

1. अनिल छिक्करा, पूर्व डिप्टी कमिश्नर दिल्ली. 2. श्री अजय शाह, टायर परिशेष के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ।
दुर्घटनाओं में टायर की भूमिका के आधार पर टायरों के अनुसंधान और विकास के लिए 3 दशकों से CIRA के साथ
मिलकर काम करते रहे हैं। 3. प्रशांत चोपड़ा, दो पहिया वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ, दो पहिया वाहनों की
सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय समर्पित किया है। 4. अनिल शर्मा, 4 दशकों से अधिक समय से विमान पायलट प्रशिक्षक।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पायलट विशेषज्ञता के आधार पर ड्राइवों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए काम करते हैं।

Nomination Open Apply Now

TRANSPORT VISHESH NEWS LIMITED www.newsparivahan.com, www.newstransport.in

कर ले।

अगर आप मानते हैं की आपने ऐसे कार्य किए जिनके आधार पर आपको सम्मान प्राप्त होना चाहिए तो जल्द से जल्द "परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र" द्वारा जारी गूगल

फार्म भर कर जमा करें। गूगल फार्म लिंक नीचे उपलब्ध है सुनहरा अवसर सम्मान प्राप्त करने के लिए गूगल फार्म भरे और पाए भारत के पहले परिवहन क्षेत्र के समाचार पत्र "परिवहन विशेष" से सम्मान

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSfuZ3djd-SaHn5EjDHDvY23xfor75p0gT60_8pwdDxeuFEiqA/viewform?usp=dialog

एक नई दिशा, एक नई सोच — सड़क सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को समर्पित अद्वितीय आयोजन

परिवहन विशेष द्वारा प्रस्तुत – सड़क सुरक्षा, नवाचार, और ट्रांसपोर्ट जगत की अग्रणी हस्तियों का संगम

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

द्वितीय वार्षिक सम्मान समारोह

दिनांक : शनिवार 17 मई 2025. प्रातः 10:00 से 7 बजे तक
स्थान : स्पीकर हॉल, कॉन्वेंट्सूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली

:- मुख्य अतिथि:-
श्री शंभू सिंह, आईएसएस
सचिव शिपिंग भारत सरकार (सेवानिवृत्त) शिपिंग मंत्रालय

:- विशेषज्ञ वक्ता:-

1. अनिल छिक्करा, पूर्व डिप्टी कमिश्नर दिल्ली. 2. श्री अजय शाह, टायर परिशेष के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ।
दुर्घटनाओं में टायर की भूमिका के आधार पर टायरों के अनुसंधान और विकास के लिए 3 दशकों से CIRA के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। 3. प्रशांत चोपड़ा, दो पहिया वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ, दो पहिया वाहनों की
सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय समर्पित किया है। 4. अनिल शर्मा, 4 दशकों से अधिक समय से विमान पायलट प्रशिक्षक।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पायलट विशेषज्ञता के आधार पर ड्राइवों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए काम करते हैं।

TRANSPORT VISHESH NEWS LIMITED www.newsparivahan.com, www.newstransport.in

संजय सागर सिंह

नई दिल्ली। परिवहन विशेष - देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र का द्वितीय वार्षिक सम्मान समारोह दिनांक : शनिवार 17 मई 2025. प्रातः 10:00 से 7 बजे तक स्थान : स्पीकर हॉल, कॉन्वेंट्सूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में किया जायेगा।

द्वितीय वार्षिक सम्मान समारोह के - मुख्य अतिथि:- श्री शंभू सिंह, आईएसएस सचिव शिपिंग भारत सरकार (सेवानिवृत्त) शिपिंग मंत्रालय होंगे।
- विशेषज्ञ वक्ता:-

1. अनिल छिक्करा, पूर्व डिप्टी कमिश्नर दिल्ली.
2. श्री अजय शाह, टायर परिशेष के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ। दुर्घटनाओं में टायर की भूमिका के आधार पर टायरों के अनुसंधान और विकास के लिए 3 दशकों से CIRA के साथ मिलकर काम करते रहे हैं।
3. प्रशांत चोपड़ा, दो पहिया वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ, दो पहिया वाहनों के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय समर्पित किया है।
4. अनिल शर्मा, 4 दशकों से अधिक समय से विमान पायलट प्रशिक्षक। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पायलट विशेषज्ञता के आधार पर ड्राइवों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए काम करते हैं।

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पायलट विशेषज्ञता के आधार पर ड्राइवों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए काम करते हैं।

परिवहन विशेष - दैनिक समाचार पत्र के द्वितीय वार्षिक सम्मान समारोह शामिल होने और देशहित समाजहित में किये गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मान प्राप्त करने हेतु आयोजकों से सम्पर्क करें।

Transport Vishesh News Limited
वेबसाइट:
www.newsparivahan.com,
www.newstransport.in

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत, ग्रेप-एक के प्रतिबंध हटे

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिली है जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप-एक के प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक्यूआई मध्यम श्रेणी में बना है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसमें और सुधार हो सकता है। इससे पहले ग्रेप-एक दो अप्रैल को लागू किया गया था।

नई दिल्ली: मौसमी उतार चढ़ाव के बीच फिलहाल प्रदूषण से राहत है। इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्व्यूएम) ने बुधस्तिवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप)-एक के प्रतिबंध हटा दिए हैं।

हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार

अगले कई दिन हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी रहेगी। इसके बाद एयर इंडेक्स में और सुधार हो सकता है। आगे आगे हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में भी पहुंच सकती है।

पिछली बार दो अप्रैल को लगा था, 28 दिन बाद हटा

पिछले वर्ष 15 अक्टूबर को ग्रेप-एक के प्रतिबंध लागू किए गए थे। 24 फरवरी को ग्रेप-दो के प्रतिबंधों को हटाया गया था। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-एक के प्रतिबंध लागू थे। तीन मार्च को इन्हें भी हटा दिया गया। कई बार ग्रेप एक लगा और हटा। पिछली बार दो अप्रैल को लगा था और बुधस्तिवार को 28 दिन बाद हटा।

आयोग की सब कमेटी की बैठक में लिया गया

फैसला

आयोग की सब कमेटी की बुधस्तिवार को बैठक हुई। इसमें दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। पिछले दो दिनो से लगातार हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। इसीलिए अब ग्रेप-एक के प्रतिबंधों को भी हटाने का फैसला किया गया।

गाजियाबाद का एक्यूआई 129 व गुरुग्राम का 249 रहा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार बुधस्तिवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 184 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है। गाजियाबाद का एयर इंडेक्स 129, गुरुग्राम का 249, ग्रेटर नोएडा का एयर इंडेक्स 121 व नोएडा का 183 रहा, जो मध्यम श्रेणी में है।



टॉलवा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.inEmail : tolwadelhi@gmail.combathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

समय और ईंधन की बर्बादी को रोकने के लिए 2027 तक दस और सड़कों को सिग्नल फ्री करने की तैयारी

दिल्ली में सड़कों पर वाहनों के कारण यात्रियों का समय और ईंधन बर्बाद होता है। इसे कम करने के लिए दिल्ली सरकार 2027 तक दस और सड़कों को सिग्नल फ्री करने की योजना बना रही है। पहले ही 60 सड़कों को सिग्नल फ्री किया जा चुका है जिससे समय और ईंधन की बचत हुई है। इसका उद्देश्य है ताकि सड़क पर न हो समय व ईंधन की बर्बादी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों वाहनों की भीड़ के कारण हर रोज यात्रियों का कीमती समय और ईंधन सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। इससे वायु प्रदूषण की समस्या भी गहराती जा रही है। सड़क पर ईंधन और समय की बर्बादी न हो तथा यातायात हर वक्त सुगम बना रहे इसके लिए दिल्ली की सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने की कवायद चल रही है। कोशिश है कि वाहनों को सड़क पर कम समय ठहरने दिया जाए, इससे न सिर्फ समय की बर्बादी पर लागाम लगेगी, बल्कि ईंधन की बर्बादी भी कम होगी। इसके लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे विस्तार और पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों सहित दिल्ली की दस प्रमुख सड़कों को व 2027 तक सिग्नल फ्री करने की तैयारी है।

2025 तक 60 प्रमुख सड़कें सिग्नल फ्री हो चुकी हैं

दिल्ली की सड़कों पर समय और ईंधन बर्बादी रोकने और यातायात व्यवस्था को



सुगम बनाने के लिए 2016 से 2025 तक 60 प्रमुख सड़कों को, उनके हिस्सों को अब तक सिग्नल-फ्री किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) और दिल्ली सरकार के संयुक्त प्रयासों से रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, मजनुं का टीला, सराय काले खां और डीएनडी फ्लाई-वे जैसे व्यस्त मार्गों पर सिग्नल फ्री फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए गए।

इन्होंने ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम किया है। इन 60 सड़कों में सिग्नेचर ब्रिज से नोएडा तक का कॉरिडोर और यमुना के समानांतर एलिवेटेड रोड शामिल हैं। दावा है कि इनसे पहले की तुलना में यात्रा समय में 25 से 30 प्रतिशत की कमी आई है। इसे सिग्नल फ्री सड़कों के

निर्बाध यातायात प्रवाह से संभव बनाया है। पर्यावरण के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी दावा है कि इससे ईंधन की बचत और वाहन उत्सर्जन में 15 से 20 प्रतिशत की कमी होने से पर्यावरण को लाभ हुआ है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी भी आई है। कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। हालांकि अब भी कुछ चुनौतियां हैं। कुछ क्षेत्रों में सिग्नल-फ्री सड़कों के कारण पैदल यात्रियों को सड़क पार करने, फुटपाथ पर चलने का स्थान न होने से सड़कों पर चलना बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। इस समस्या को दूर करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं।

पहले की दिक्कतें, अब की सुविधाएं

पहले: लगातार सिग्नल पर रुकने से समय बर्बाद, ट्रैफिक जाम और ईंधन की अधिक खपत।
अब: निर्बाध यातायात प्रवाह, कम यात्रा समय, बेहतर कनेक्टिविटी।
पहले: प्रदूषण और शोर।
अब: कम उत्सर्जन और शांत यात्रा।
लाभ
समय की बचत: सिग्नल फ्री सड़कों से यात्रा समय 20 से 30 प्रतिशत कम हुआ।
ट्रैफिक जाम में कमी: भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात प्रवाह सुगम हुआ।
ईंधन की बचत: रुकने-चलने की स्थिति कम होने से ईंधन खपत घटी।
पर्यावरणीय लाभ: वाहन उत्सर्जन में कमी आई।

NRAI ने नई दिल्ली में फूड डिलीवरी समिट 2025 के चौथे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया

सुषमा रानी



नई दिल्ली। भारतीय रेस्तरां उद्योग की आवाज नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने आज नई दिल्ली के ले मेरिडियन में NRAI फूड डिलीवरी समिट 2025 के चौथे संस्करण का समापन किया। "अपने फूड बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नए विचार प्रदान करना" थीम के साथ, इस समिट में भारत के फूड डिलीवरी इकोसिस्टम से 2000+ से अधिक प्रमुख हितधारकों ने एक दिन के लिए अंतर्दृष्टि, नेटवर्किंग और भविष्य की सोच के साथ एक साथ आए।

इस समिट का उद्घाटन माननीय सांसद बांसुरी स्वराज द्वारा दीप प्रज्वलन समारोह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति से और भी सम्मानित किया गया।

सहयोग और विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में काम करने वाले इस शिखर सम्मेलन में रेस्तरां उद्योग, क्लाउड किचन संचालकों, एग्ग्रेगटर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और तकनीकी

उद्योगियों की शीर्ष आवाजों के साथ आई। विकसित हो रहे उपभोक्ता परिदृश्य, हाइपर-दक्षता की बढ़ती मांग और टिकाऊ डिलीवरी मॉडल को तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की गई।

एनआरआई के अध्यक्ष और निरंतर प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संकट के समय में लोगों को मुनाफे से ऊपर रखने के लिए एनआरआई नेतृत्व, विशेष रूप से एनआरआई अध्यक्ष सागर दरवानी और एनआरआई उपाध्यक्ष जोरावर कालरा की सराहना की। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे एनआरआई सदस्यों ने कोविड के दौरान एक महीने में 1 करोड़ मुफ्त भोजन का योगदान दिया और सुरक्षित रूप से काम करने के लिए

सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से टीका लगाने के माननीय प्रधान मंत्री मोदी के आह्वान पर अपने पूरे कर्मचारियों को टीका लगाया।

शिखर सम्मेलन में बोलेते हुए, कोका कोला इंडिया के मुख्य ग्राहक अधिकारी, अभिषेक गुप्ता ने कहा, "रिश्तेदार सम्मेलन में बोलेते हुए, कोका कोला इंडिया के मुख्य ग्राहक अधिकारी, अभिषेक गुप्ता ने कहा, "कोका-कोला में, हम सार्थक अनुभव बनाने और हर उपभोक्ता टचपॉइंट पर मूल्य प्रदान करने से प्रेरित हैं, और खाद्य वितरण दोनों के लिए एक प्रभावी उपकरण हैं। चूँकि उपभोक्ता प्राथमिकताएँ विकसित होती रहती हैं, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चपलता, नवाचार और जिम्मेदारी के साथ प्रतिक्रिया करना

महत्वपूर्ण है। हमें NRAI शिखर सम्मेलन का समर्थन करने पर गर्व है, जो खुले संवाद और समाधानों को बढ़ावा देता है जो रसोई से लेकर ग्राहकों तक पूरी मूल्य श्रृंखला को लाभान्वित करते हैं।"

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए, रेस्टोरेंट्स के सह-संस्थापक और सीईओ, श्री आशीष तुलसियान ने कहा, "तकनीक अब खाद्यवितरण में सहायक कार्य नहीं है; यह रीढ़ की हड्डी है। एक प्रमुख आकर्षण कोका-कोला फूडमार्क्स 2.0 का आधिकारिक शुभारंभ था, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित पाक स्थलों का जन्म मनाने वाली एक पहल है। प्रमुख सत्रों में "टेक एज ए मार्जिन मल्टीप्लायर", "रीलो के साथ मार्जिन जो मायने रखते हैं", और पिज का सत्र "एग्ग्रेगटर निर्भरता के लिए विजयी विकल्प" शामिल थे। "द लास्ट माइल इज द लॉन्गेस्ट" और "क्विक गैरिज" पर चर्चाओं ने महत्वपूर्ण वितरण मुद्दों को संबोधित किया। मिस्टर टिक्कू, सिद्धार्थ जोगानी, रावब जोशी और अन्य लोगों ने प्रभावशाली मार्केटिंग, लाभप्रदता और स्केलिंग

रणनीतियों के बारे में बात की। इनोवेशन शोकेस, फायरसाइड चैट और नेटवर्किंग क्षेत्रों ने भविष्य के उद्योग विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

प्रतिभागियों ने यह भी बताया कि उपभोक्ता अपेक्षाएँ कैसे बदल रही हैं, खासकर गति, स्थिरता, पारदर्शिता और सुविधा के मामले में। उद्योग के नेताओं ने दीर्घकालिक लाभप्रदता को आगे बढ़ाने में डिजिटल अपनाने, डेटा एनालिटिक्स, हाइपरलोकल रणनीतियों और मानकीकृत प्रथाओं के महत्व पर जोर दिया।

शिखर सम्मेलन का समापन एक मजबूत कार्रवाई के आह्वान के साथ हुआ, जिसमें सभी खिलाड़ियों से विकास को बनाए रखने और बदलती उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने, नवाचार करने और बोर्ड भर में मानकीकरण करने का आग्रह किया गया। NRAI भारत के खाद्य सेवा उद्योग में 4वें खाद्य वितरण शिखर सम्मेलन को एक गौरवपूर्ण क्षण बनाने के लिए सभी उपस्थित लोगों, वक्ताओं, प्रायोजकों और भागीदारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

जातीय जनगणना सामाजिक न्याय के लिए मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: पेरिका सुरेश



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया मेंबर पेरिका सुरेश ने केंद्र की मोदी सरकार एवं उनके मंत्रिमंडल द्वारा जातीय जनगणना का ऐतिहासिक निर्णय लेने पर बधाई देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है जो सामाजिक न्याय के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। श्री सुरेश ने कहा कि सरकार समाज के दबे कुचले एवं अतिम पंक्ति में खड़े लोगों को भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास में लगी है और इसी के तहत जातीय जनगणना का निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। उन्होंने ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को मुंह मीठा कराकर बधाई दी और कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान

1931 में जातीय जनगणना कराई गई थी उसके उपरांत जातीय जनगणना की मांग के बावजूद भी किसी भी सरकार ने ऐसा करने के प्रति अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। श्री सुरेश ने कहा कि जातीय जनगणना के बाद यह पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है और उसी अनुपात में उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। श्री सुरेश ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ओबीसी मोर्चा के जातीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल एवं ऐतिहासिक निर्णय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

दिल्ली में गर्मी से राहत की नई पहल: कश्मीरी गेट ISBT पर लगी पहली स्मार्ट वॉटर डिस्पेंसिंग मशीन

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली की भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए आम जनता को शुद्ध और ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। आज कश्मीरी गेट ISBT पर पहली स्मार्ट वॉटर डिस्पेंसिंग मशीन का जल मंत्री प्रवक्ता साहिब वर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया। यह परियोजना दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अंतर्गत चलाई जा रही है।

इस मशीन का उद्घाटन दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने किया। उन्होंने मशीन का निरीक्षण किया, इसकी कार्यप्रणाली को समझा और उपस्थित अधिकारियों को इस पहल को पूरे शहर में लागू करने के निर्देश दिए।

यह स्मार्ट मशीन आधुनिक तकनीक से युक्त है और 24x7 आम जनता को ठंडा, शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएगी। हीट एक्शन प्लान 2025 के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य न केवल गर्मी से राहत देना है, बल्कि दिल्ली को स्मार्ट और जनकल्याणकारी शहर के रूप में विकसित करना भी है।

इस अवसर पर जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा:

"हम चाहते हैं कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति प्यास न रहे। यह स्मार्ट वॉटर डिस्पेंसिंग मशीन



सिर्फ एक तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि जनसेवा की भावना से जुड़ी एक क्रांतिकारी पहल है। आने वाले समय में हम दिल्ली के प्रमुख स्थलों पर ऐसी कई मशीनें लगाएंगे, जिससे हर नागरिक को साफ, ठंडा और मुफ्त पानी उपलब्ध हो सके।"

स्मार्ट वॉटर डिस्पेंसिंग मशीन की प्रमुख खूबियाँ:

- जनरल स्पेसिफिकेशन:
- आकार: 4x4 फीट का बेस, लगभग 7 फीट ऊंचाई

- शुद्धिकरण प्रणाली: RO/UF आधारित, कम से कम 100 लीटर प्रति घंटा
- भंडारण क्षमता: कुल 800 लीटर (कच्चा और शुद्ध जल)
- कूलिंग: इन-बिल्ट चिलर (15°C - 20°C तापमान बनाए रखता है)
- आउटलेट: 4 टॉटियाँ
- निर्माण और अनुपालन:
- मानक: IS 10500 के अनुसार पीने योग्य जल
- बॉडी: फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील 304,

गैल्वेनाइज्ड/पाउडर कोटेड, एंटी-रस्ट

● मॉड्यूलर डिजाइन: आसान इंस्टॉलेशन व ट्रांसपोर्टेशन (2-3 लोगों द्वारा संभाला जा सकता है)

● मौसम प्रतिरोधी: दिल्ली की गर्मी, धूल और बारिश के अनुसार अद्विकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स:

- डिजिटल डिस्पेंस: 43" वाटरप्रूफ, डे-लाइट रोडेबल स्क्रीन
- IoT सेंसर: जल आपूर्ति, TDS, फिल्टर स्टेटस और टैंक लेवल की निगरानी
- AI कैमरा: उपयोगकर्ता गिनती के लिए
- क्लाउड डैशबोर्ड: रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग
- कनेक्टिविटी: इनबिल्ट Wi-Fi/4G
- CMS: रिमोट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम

4. मुख्य लाभ:

- 24x7 ठंडे और शुद्ध पानी की मुफ्त सुविधा
- लगातार मॉनिटरिंग से गुणवत्ता सुनिश्चित
- भीषण गर्मी में यात्रियों, राहगीरों और श्रमिकों के लिए राहत

इस स्मार्ट समाधान से दिल्ली के लाखों नागरिकों को लाभ मिलेगा और भविष्य में इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, अस्पताल, स्कूल, और बस स्टैंडों पर भी मशीनें स्थापित की जाएंगी।

जाति जनगणना पारदर्शी, समावेशी और राजनीतिक दखल से मुक्त होनी चाहिए: प्रोफेसर सलीम इंजीनियर

सुषमा रानी

नई दिल्ली, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है।

मौडिया को जारी एक बयान में जमाअत उपाध्यक्ष ने कहा, रहम आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं। जाति अभी भी भारत में एक मजबूत सामाजिक संरचना है जो शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच को आकार देती है। यह पिछड़ी जातियों, दलितों और आदिवासियों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए एक सामाजिक, कानूनी, प्रशासनिक और नैतिक आवश्यकता है। यह सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को निगरानी के लिए सटीक डेटा प्रदान करेगा और इन समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद करेगा। यह सर्वविधित तथ्य है कि केवल मापी गई चीज का ही प्रबंधन किया जा सकता है, और इसलिए सूचित नीति निर्माण और समावेशी विकास के लिए

जातिगत डेटा आवश्यक है। जाति जनगणना इन उपेक्षित समुदायों के लिए सकारात्मक व्यवहारिक नीतियों की निगरानी और उन्हें मजबूत करने के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध कराएगी, विशेष रूप से बढ़ते निजी क्षेत्र और घटती सरकारी नौकरियों के संदर्भ में।

सरकार के निर्णय को स्वीकार करते हुए प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने जाति जनगणना कराने में सरकार की पूर्ण अतिरिक्त पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "जैसा कि संसद में दिए गए आधिकारिक बयानों से पता चलता है, सरकार अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से परे जाति जनगणना के पूरी तरह से खिलाफ थी। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अंततः इसकी प्रभावशीलता को स्वीकार कर लिया है।" खराब संसूच और क्रियान्वयन के कारण 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना की विफलता एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हालांकि, हमारा मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने और अनुसूचित 14, 15 और 16 के तहत संवैधानिक गारंटी को बरकरार रखने के लिए यह प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और

राजनीतिक दखल से मुक्त होनी चाहिए।

जमाअत उपाध्यक्ष ने आगे कहा, "सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समयसीमा जारी की जानी चाहिए। जाति जनगणना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए। जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय होना चाहिए न कि राजनीतिक लाभ। टेक्नोलॉजी का उपयोग, जैसे कि प्री-लोडेड जाति विकल्पों के साथ इंटरनेट-सक्षम डिवाइस, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करेगा। हम उन लोगों से सहमत नहीं हैं जो जाति जनगणना का विरोध करते हैं और दावा करते हैं कि यह विभाजन को मजबूत करती है या प्रशासनिक रूप से जटिल है। भारत की जनगणना में पहले से ही धर्म और भाषा की गणना होती है, तथा 1951 से एससी/एसटी की गणना होती आ रही है। इनसे संघर्ष को बढ़ावा नहीं मिला है। गणना संभव है, जैसा कि विहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। हम सभी हितधारकों से इस परिवर्तनकारी अन्याय का समर्थन करने का आह्वान करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय मिलेगा।"

क्रॉम्पटन ने एम.ई.डी.ए से सौर जल पंप ऑर्डर के साथ हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया

सुषमा रानी

नई दिल्ली, "ऊर्जा विकास एजेंसी ने 10.60 करोड़ मूल्य के 433 सौर जल पंपों का ऑर्डर देकर नवीकरणीय ऊर्जा में क्रॉम्पटन की भूमिका को और भी मजबूत कर दिया"

पंप उद्योग में अपनी नवोन्मेषी समाधानों के लिए प्रसिद्ध क्रॉम्पटन ग्रीन्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी को प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत सौर जल पंपिंग प्रणाली के लिए ऑर्डर मिला है।

इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए, कंपनी को महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) से महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर 10.60 करोड़ से अधिक मूल्य के सौर फोटोवोल्टिक जल पंपिंग सिस्टम (एसपीडब्ल्यूपीएस) के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परिवहन, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए लेंटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है। इस ऑर्डर के साथ, क्रॉम्पटन विश्वसनीय और कुशल सौर जल पंपिंग समाधानों के माध्यम से टिकाऊ खेती को सुलभ करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना जारी रखेगा।

क्रॉम्पटन के पंप टिकाऊपन और प्रदर्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो पांच-चरणीय उत्पाद विकास प्रक्रिया, उन्नत विनिर्माण क्षमताओं और गहन अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञता से सुज्जित हैं। अगले कुछ वर्षों में पीएम-कुसुम योजना के तहत अधिक से अधिक सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने की योजना के साथ, क्रॉम्पटन इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।

अगले कुछ वर्षों में पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत और अधिक सौर ऊर्जा चालित पंप लगाने की योजना के साथ, क्रॉम्पटन ऊर्जा दक्षता श्रेणी में प्रभाव डालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के माध्यम से कृषि में सतत प्रगति को बढ़ावा देने की क्रॉम्पटन की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-बी के हिस्से के रूप में यह पहल किसानों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने में सीधे योगदान देती है — जिससे आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों

लाभ होते हैं। यह प्रगति ऐसे समय में हुई है जब भारत के सबमर्सिबल वाटर पंप बाजार में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जो कृषि, ग्रामीण जल आपूर्ति, शहरी बुनियादी ढांचे और औद्योगिक उपयोग जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग से प्रेरित है।

कृषि में, गहरे कुओं की सिंचाई के लिए निरंतर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में सबमर्सिबल पंप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं - खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा असमान होती है-नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ता जोर विशेष रूप से ग्रामीण और ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित समाधानों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा दे रहा है।

इस अवसर पर रजत चोपड़ा, बिजनेस हेड - होम इलेक्ट्रिकल्स एवं पंप्स, क्रॉम्पटन ग्रीन्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंपों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्टेनलेस स्टील की जंग-रहित बनावट लिमिटेड ने कहा, "हम पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) के साथ साझेदारी करके मौखिक महसूस कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत और टिकाऊ पंपिंग समाधानों को प्रदान करने के प्रयासों के साथ-साथ है। यह ऑर्डर हमारे सौर ऊर्जा पर आधार

कार यूजर्स के लिए क्यूबो ने लॉन्च किए तीन डैशकैम, जानें क्या है खासियत और कितनी है कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में जिस तरह से सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उससे बचने के लिए कई निर्माता Dashcam को ऑफर कर रहे हैं। Qubo की ओर से भी तीन नए Dashcam को लॉन्च किया गया है। इनको किस तरह की खासियत के साथ लाया गया है। किस कीमत पर इनको ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। वाहनों की सुरक्षा के लिए लगातार बाजार में कई नई एक्सेसरीज को ऑफर किया जाता है। Qubo कंपनी की ओर से कारों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तीन नए DashCam को लॉन्च किया है। इन तीनों Dash Cam में किस तरह की खासियत को दिया गया है। इनको किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च हुए नए Dashcam

Qubo की ओर से भारतीय बाजार में तीन नए डैशकैम को लॉन्च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से कारों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए डैशकैम बाजार में लॉन्च किए गए हैं। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इनको सुपर एडवांस सोनी Starvis 2 सेंसर के साथ ऑफर किया जा रहा है।



कौन से डैशकैम हुए लॉन्च

Qubo की ओर से जिन तीन डैशकैम को लॉन्च किया गया है, उनमें Pro 3k, Pro 2.7k और Pro 2k शामिल हैं। निर्माता की ओर से Pro 3k को Sony Starvis 2 सेंसर के साथ लाया गया है, जिससे कम रोशनी में भी अच्छी इमेज कैप्चर की जा सकती है। इसके साथ ही यह तीनों कैमरे एक टीबी तक की स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं।

अधिकारियों ने कही यह बात

क्यूबो के फाउंडर और सीईओ निखिल राजपाल ने बताया कि आज सड़कें बहुत बेहतर होने के बावजूद, ड्राइविंग उतना सुखद अनुभव नहीं है जितना हम चाहते हैं - इसका मुख्य

कारण लगातार बढ़ता ट्रैफिक है। सड़क पर गुस्सा और असुरक्षित ड्राइविंग की बढ़ती घटनाएं, जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं, ने उन उपयोगकर्ताओं द्वारा डैशकैम की मांग को बढ़ावा दिया है जो हर समय सड़क पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। तीन नए डैशकैम को पेश करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा विकल्प के साथ, हम अधिक उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करके बाजार में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं।

कितनी है कीमत

निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक Pro 2k को फिलहाल 3990 रुपये,

Pro 2.7k को 7990 और Pro 3k को 10990 रुपये की कीमत (Qubo Smart Dashcam Price) पर ऑफर किया जा रहा है।

क्या मिलता है फायदा

डैशकैम कार के लिए एक जरूरी एक्सेसरीज के तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कार चलते हुए इनमें जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है वह हादसा होने जैसी स्थितियों में आपके लिए एक सबूत की तरह काम करती है और आपको परेशानी से बचा भी सकती है। इसकी उपयोगिता समझते हुए कुछ वाहननिर्माताओं की ओर से इसे अपनी कारों में सेफ्टी फीचर के तौर पर ऑफर भी किया जा रहा है।

नई एमजी विंडसर टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट; एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्ट, बड़ी बैटरी समेत V2L फीचर्स से होगी लैस



परिवहन विशेष न्यूज

नई एमजी विंडसर को हरियाणा के गुरुग्राम में टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किया गया है। टेस्टिंग मॉडल पर Pro की ब्रांडिंग देखने के लिए मिली है। जिससे उम्मीद की जा रही है कि इसका नाम MG Windsor Pro हो सकता है। नई MG Windsor बड़ी बैटरी पैक नए ADAS फीचर्स समेत V2L (व्हीकल टू लोड) फीचर्स से लैस हो सकती है।

नई दिल्ली। MG Windsor के लॉन्च होने के बाद से ही इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। जिसकी वजह यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के साथ ही भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार भी बन गई है। वहीं, अब कंपनी इसके नए वेरिएंट को लेकर आने वाली है, जिसमें बड़ा बैटरी पैक देखने के लिए मिलेगा। इसे बड़ा बैटरी पैक मिलने के बाद यह करीब 450 किमी से ज्यादा की रेंज दे सकती है। इसके नए

वेरिएंट को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किया गया है। आइए जानते हैं कि नई MG Windsor के टेस्टिंग मॉडल में क्या कुछ देखने के लिए मिला।

हो सकता है ये नाम ?

नई MG Windsor को हरियाणा के गुरुग्राम में टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसपर Pro की ब्रांडिंग देखने के लिए मिली है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि इसका नाम MG Windsor Pro हो सकता है। इसमें कई नए फीचर्स और बेहतरीन सुविधाओं के साथ ही बड़ी हुई रेंज देकर के लिए मिलेगी।

हाल में आने वाली Windsor EV को भारतीय ग्राहकों ने काफी पसंद किया है, जिसकी वजह से यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। इसकी बिक्री और बढ़ाने के लिए कंपनी इसे अब अपडेट करने जा रही है। इसमें बड़ा बैटरी पैक देखने के लिए मिल सकता है। इसमें ZS EV जैसा ही 50.3 kWh बैटरी पैक ऑफर दिया जा सकता है, जो फुल चार्ज

होने के बाद 450 किमी से ज्यादा की रेंज दे सकता है। मौजूदा मॉडल में 38kWh बैटरी पैक ऑफर किया जाता है, जो फुल चार्ज होने के बाद 331 किमी तक का रेंज देती है।

क्या मिलेगा नया ?

नई MG Windsor में V2L (व्हीकल टू लोड) फीचर और ADAS सूट के कई नए फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके ADAS सूट में ऑटोनॉमस ड्राइवर एड फीचर जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, इंटेलेजेंट हाई बीम असिस्ट और कई फीचर्स को शामिल किया जा सकता है।

मौजूदा विंडसर ईवी में लाउंज जैसी सीटिंग, 2,700 मिमी लंबा व्हीलबेस, प्रीमियम टच और मटीरियल का अनुभव, 15.6 इंच का ग्रैंडव्यू डिस्प्ले, इन्फिनिटी व्यू ग्लास रूफ, 256 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग पैड, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले, वॉलटेज फ्रंट सीट, पावर्ड ड्राइवर सीट और 604L तक का बूट स्पेस दिया जाता है।

भारत में जल्द लॉन्च होगी 2025 बजाज डोमिनार 400, मिलेंगे नए फीचर्स समेत कलर ऑप्शन



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। बजाज ऑटो भारतीय बाजार में जल्द ही नई Bajaj Dominar 400 को लॉन्च करने वाली है। यह लॉन्च होने से पहले ही डीलरशिप तक पहुंचने लगी है। Dominar 400 को लंबे समय के बाद अपडेट मिलने वाला है। इसे नया कलर ऑप्शन के साथ ही नए फीचर्स के साथ अपडेट किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि 2025 Bajaj Dominar 400 को किस फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

क्या मिलेगा नया ?

नई Bajaj Dominar 400 में पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है, जो NS400Z में देखने के लिए मिलता है। इसमें नए क्लस्टर के साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी जा सकती है, इस फीचर को पहली बार इसमें शामिल किया जाएगा।

इसमें फ्यूल टैंक पर मिलने वाले टेल-टेल क्लस्टर की जगह पर USB चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। वहीं, नए स्ट्रूमेंट क्लस्टर को नियंत्रित करने के लिए, बजाज ने स्विचगियर पर एक D-पैड है जिसका उपयोग इस क्लस्टर को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।

इतना ही नहीं 2025 Bajaj Dominar 400 में राइड-बाय-वायर और ABS मोड को भी शामिल किया जा सकता है। बजाज ऑटो इसे नए कलर स्कीम भी दे सकता है। इसके इंजन को BS6 P2 OBD2B उत्सर्जन मानकों के अनुरूप किया जा सकता है।

क्या नहीं बदलेगा ?

2025 Bajaj Dominar 400 में किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव देखने के लिए नहीं मिल सकता है। इसमें पहले की तरह ही 373.3cc सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है, जो 39 bhp की पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके इंजन को पहले की तरह ही 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा।

इसमें पहले की तरह ही विंडस्क्रीन, नकल गार्ड, एक रियर लगेज रैक और एक पिलियन बैकरेस्ट देखने के लिए मिल सकता है। इसके टूरिंग कैपेसिटी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसे टूरिंग एक्सेसरीज के साथ मानक रूप से फिट किए गए एकमात्र वेरिएंट में पेश किया जाना जारी रखा जा सकता है।

मौजूदा मॉडल की एक्स-शूमेर कीमत 2.26 लाख रुपये है। इसे अपडेट मिलने बाद इसकी कीमत में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है।

2025 बजाज डोमिनार 400 भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इसके लॉन्च होने से पहली यह डीलरशिप तक पहुंचने लगी है। जिसके मुताबिक इसमें कई बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इन बदलावों में नया कलर समेत ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB चार्जिंग पोर्ट तक देखने के लिए मिल सकता है। इसके इंजन किसी तरह का बदलाव देखने के लिए मिलेगा।

मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2025 में की सबसे ज़्यादा कारों की बिक्री, जानें किस सेगमेंट में रही सबसे ज्यादा मांग

परिवहन विशेष न्यूज

मारुति सुजुकी की बिक्री अप्रैल 2025 भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki हर महीने लाखों की संख्या में वाहनों की बिक्री करती है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बीते महीने के दौरान कुल कितनी कारों की बिक्री की गई है। इनमें से कितनी कारों का एव सपोर्ट किया गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिक्री कैसी रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करने वाली प्रमुख वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से April 2025 में बिक्री की जानकारी दी गई है। निर्माता से मिली जानकारी के मुताबिक बीते महीने कितनी यूनियंस की बिक्री हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा प्रदर्शन रहा है। एक्सपोर्ट के मामले में बीता महीना (Maruti Suzuki sales April 2025) कैसा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितनी हुई बिक्री

मारुति सुजुकी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2025 के दौरान निर्माता की ओर से 27911 यूनियंस का एक्सपोर्ट किया गया है। जबकि अप्रैल 2024 में यह संख्या 22160



Maruti Suzuki की ओर से बीते महीने के दौरान हुई बिक्री की रिपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक April 2025 के दौरान निर्माता ने 1.79 लाख यूनियंस की बिक्री की है। जबकि पिछले साल यह संख्या 1.68 लाख यूनियंस की थी।

कितना हुआ एक्सपोर्ट

मारुति सुजुकी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2025 के दौरान निर्माता की ओर से 27911 यूनियंस का एक्सपोर्ट किया गया है। जबकि अप्रैल 2024 में यह संख्या 22160

यूनियंस की थी।

किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा मांग

निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कॉम्पैक्ट सेगमेंट की कारों की सबसे ज्यादा मांग रही है। इस सेगमेंट में निर्माता ने बीते महीने 61591 यूनियंस की बिक्री की है। जबकि यूनियंस की बिक्री 59022 यूनियंस रही है। मिनी सेगमेंट में 6332 यूनियंस की बिक्री हुई है। वहीं अप्रैल 2025 में ईको की 11438 और सियाज की 321 यूनियंस की बिक्री की गई है। लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सुपर कैरी

की बीते महीने 3349 यूनियंस की बिक्री हुई है।

2024 में कैसी थी मांग

अप्रैल 2024 के दौरान मारुति सुजुकी की 56953 यूनियंस कॉम्पैक्ट कारों की मांग रही थी। यूनियंस सेगमेंट की 56553 मांग रही थी। मिनी सेगमेंट में 11519, ईको की 12060 और सियाज की 867 यूनियंस की बिक्री देशभर में हुई थी। वहीं एलसीवी सेगमेंट में सुपर कैरी की 2496 यूनियंस की बिक्री पिछले साल इसी अवधि में हुई थी।

कैसा है पोर्टफोलियो

निर्माता मिनी सेगमेंट में Alto, S-Presso की बिक्री करती है। कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में मारुति की ओर से Baleno, Celerio, Dzire, Ignis, Swift, WagonR को ऑफर किया जाता है। यूनियंस की बिक्री में निर्माता की ओर से Brezza, Ertiga, Fronx, Grand Vitara, Invicto, Jimny, XL6 की बिक्री की जाती है। वैन सेगमेंट में ईको और मिड साइज सेगमेंट में सियाज को ऑफर किया जाता है। इसके अलावा लाइट कमर्शियल सेगमेंट में निर्माता की ओर से सुपर कैरी की बिक्री भी की जाती है।

बीएमडब्ल्यू आर 1300 आर.टी भारत में जल्द होगी लॉन्च, 10.25-इंच टीएफटी डिस्प्ले समेत मिलेंगे एडवांस फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

BMW R 1300 RT भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इसके लॉन्च होने से पहले कंपनी ने डिटेल्स जारी कर दी है। जिसके मुताबिक इसमें ट्रेवशन कंट्रोल इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल और एक्टिव क्रूज कंट्रोल और फॉरवर्ड और रियर कोलिजन वार्निंग एक्टिव ब्रेकिंग और लेन स्वे वार्निंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। वहीं इसमें ऑडियो सिस्टम के साथ 10.25-इंच TFT डिस्प्ले भी मिलेगा।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में BMW अपनी 1300cc की दो मोटरसाइकिल को लॉन्च करने वाली है। इसमें से एक BMW R 1300 RT होने वाली है। इसे लंबी दूरी के सफर के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए

हैं, जिसकी वजह से सफर और भी ज्यादा आरामदायक हो जाता है। आइए जानते हैं कि BMW R 1300 RT किस फीचर्स से लैस रहने वाली है ?

कैसा होगा इंजन ?

इसमें 1300cc का ट्विन-सिलेंडर, एयर और लिक्विड-कूल्ड इंजन का इंस्टेमाल किया गया है। यह इंजन 145hp की पावर और 49Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

इसमें R 1300 GS के समान ही मेन-फ्रेम दिया गया है और रियर सबफ्रेम भी R 1300 RS जैसा ही है। इसके फ्रेम को EVO टेलीलेवर फ्रंट और EVO पैरालेवर रियर सस्पेंशन द्वारा सस्पेंड किया गया है। इसमें ब्रेकिंग के लिए रेडियली

माउंटेड फोर-पिस्टन कैलिपर्स के साथ ट्विन फ्रंट डिस्क और टू-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स के साथ रियर डिस्क दिया गया है। इसके दोनों टायरों पर R और RS के समान ही 17-इंच कास्ट एल्यूमीनियम अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसका वजन पहले के मुकाबले 1.4 किलोग्राम कम हो जाता है।

मिलेगा ट्विन 27-लीटर टूरिंग केस

BMW R 1300 RT में ट्विन 27-लीटर टूरिंग केस दिए जाएंगे। इसमें 780 मिमी का एक आसान स्टोरेज मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के साथ संगत दोनों हैं। इसके अलावा, 39 लीटर और 54 लीटर की कैपेसिटी वाले दो टॉपकेस का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके पीछे बैठने वाले के लिए एक गैम बैकरेस्ट मिलेगा। इसमें

मिलने वाला 54-लीटर लगेज कम्पार्टमेंट भी इलेक्ट्रिक है।

मिलेंगे ये फीचर्स

BMW R 1300 RT में ट्रेवशन कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल और एक्टिव क्रूज कंट्रोल और फॉरवर्ड और रियर कोलिजन वार्निंग, एक्टिव ब्रेकिंग और लेन स्वे वार्निंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसमें तीन राइडिंग मोड इको, रेन और रोड के साथ आने वाली है। इसके ऑप्शनल राइडिंग पैकेज प्रो में डायनेमिक और डायनेमिक प्रो मोड को शामिल किया जाएगा। इसमें ऑडियो सिस्टम के साथ 10.25-इंच TFT डिस्प्ले भी मिलेगा।

इसे चाल अलग-अलग वेरिएंट में लेकर आया जाएगा। हर वेरिएंट को अलग कलर दिया गया है, जो बेसिक वेरिएंट, ट्रिपल ब्लैक, इप्लस और ऑप्शन 719 कैमराग है।



पत्रकारिता : चुनौती एवं भविष्य



विजय गर्ग

हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर यदि सामाजिक सरोकार रखने वाली निष्पक्ष पत्रकारिता तथा पीत पत्रकारिता के बारे में बात न हो, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की महत्त्वता का आंकलन नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिदृश्य में पीत पत्रकारिता की प्रबलता और स्वार्थसाधनी राजनीति निजी महत्त्वकांक्षा के चलते पत्रकारिता मिशन न रहकर व्यवसाय बन चुका है। स्वतंत्रता संग्राम की ध्वजवाहक रही हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समय में अपना अस्तित्व खोने लगी है और यही कारण है कि हमें केवल हर वर्ष 30 मई के दिन ही हिंदी पत्रकारिता का महत्व पता चलता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाने की सार्थकता, हिंदी पत्रकारिता को समझने और मानने से सिद्ध हो सकती है। वर्तमान परिदृश्य में जहाँ अंग्रेजी बोलना व पढ़ना प्रतिष्ठा प्रतिक समझा जाने लगा है वहीं एक समय में हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम में ध्वजवाहक का कार्य किया था। देश की कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हिंदी समाचार पत्र पढ़ता है परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अंग्रेजी अखबार में छपने वाली खबर की प्रामाणिकता हिंदी समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक मानी जाने लगी है। हालांकि आधुनिकता की दौड़ में हिंदी पत्रकारिता की प्राथमिकता कदाचित न हो परन्तु प्रजाति कदापि नहीं है। हिंदी माध्यम से जुड़े समाचारपत्रों और डिजिटल माध्यमों में अब हिंग्लिश का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। जिसके चलते इस आधुनिक दौर में हिंदी पत्रकारिता को बचाए रखने और पाठकों को हिंदी समाचार पत्रों के साथ जोड़े रखने के लिए अत्यधिक संघर्ष किया जा रहा है। पंडित जगल किशोर और राजा राममोहन राय की ओर से सामाजिक सरोकार और निष्पक्ष पत्रकारिता का यह मिशन मूल उद्देश्य से अनिभियत दिखाई दे रहा है और यह सम्पूर्ण देश के लिए चिंता का विषय है।

विजय गर्ग

हम सभी के जीवन में प्रार्थनाओं का महत्त्व बहुत अधिक रहा है। यही कारण है कि शुरुआत से ही प्रार्थनाएं हमारे जीवन का केन्द्र बनीं रही हैं। फिर वह विद्यालय में कक्षाओं के शुरू और अंत में नैतिक मूल्यों और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत हों या फिर हर दिन सुबह और सांध्य बेला में भजन मंडलियों, दोस्तों और परिवार के साथ लयबद्ध कर भक्ति रस, काव्य रस तो कभी क्षेत्रीय बोलियों में डूबी रचनाएं हों। प्रार्थनाएं हमें कभी कबीर, रहीम, मीरा के दोहों से गुजरने का मौका देती हैं तो कभी रैदास, नानक, सूफी जैसे महान संतों, चिंतकों के बीच बैठा देती हैं। हम निर्गुण भजनों के अर्थों को समझ जीवन में ठहराव महसूस करने लगते हैं, जैसे विचलित मन को किसी ने सही दिशा में एकाग्रचित्त कर दिया हो। प्रार्थनाएं कलात्मक होती हैं। फिल्मों में भी लगातार प्रार्थनाओं का उपयोग किया गया है, जो बहुत लोकप्रिय भी हुईं।

यकीनन जहाँ प्रार्थनाएं की जा रही होती हैं, वहाँ मनुष्य के भीतर के अच्छे गुणों को उभरने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। हम यहाँ लाउडस्पीकर पर शोर मचाती, अपनी भव्यता, विलासिता सबको दिखाते, खुद को श्रेष्ठतर साबित करने की होड़ में कोलाहल में तब्दील हो चुकी प्रार्थनाओं, भजनों की बात नहीं कर रहे हैं। वे तो बस मनुष्य की जिद को संतुष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं, जो कि केवल मैं और मेरे तक ही सीमित हैं। जबकि प्रार्थनाएं पूरी सृष्टि को अपना समझने की उदारता हमारे भीतर लेकर आती हैं। हम सादगी में लिपटी उन मद्धिम ध्वनि तरंगों की बात कर रहे हैं, जो हमें मनुष्यता, भाईचारे का पाठ पढ़ा जाती हैं। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक रूप से मनुष्य को बेहतर इंसान बनाने के लिए हमेशा से कार्यरत रही हैं। वे हमारे भीतर का उजला पक्ष रेखांकित कर देती हैं, हम अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में महसूस करने लगते हैं। उनके होने से आबोहवा

विजय गर्ग

मानसिक कल्याण को अब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए माध्यमिक नहीं माना जा सकता है। जैसे-जैसे सरकारी पहल आकार लेती है और जन जागरूकता बढ़ती है, हमारे देश के मानसिक स्वास्थ्य और इसके कर्म, हमारे भविष्य की रक्षा के लिए सामूहिक, दयालु प्रतिक्रिया का समय आ गया है।

एक पुरानी कहावत है कि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर की ओर जाता है - मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सका! महामारी के बाद से, हम मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में भारी वृद्धि देख रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि बड़ी संख्या में लोग आज असहनीय तनाव, अवसाद और चिंता से पीड़ित हैं। यह समान रूप से ध्यान देने के विषय में है कि ये बीमारियाँ उम्र के स्पेक्ट्रम में प्रभावित हो रही हैं, चाहे वे छात्र हों, युवा वयस्क हों या बुजुर्ग।

जब हम मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों को देखते हैं, तो यह टैटो के एक टन से प्रभावित होने जैसा है। इस मुद्दे की हद तक है कि भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या कर रहा है।

देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती आत्महत्या मौतों पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में परिसरों में छात्र आत्महत्या से होने वाली मौतों को रोकने और उनके मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को दूर करने के लिए एक तंत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया।

पीठ ने कहा कि 2021 के लिए राष्ट्रीय अपराध

वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता का स्वरूप एवं उसका महत्व बदल गया है। राजनैतिक महत्वाकांक्षा के चलते सूचना देने वाले विभिन्न माध्यमों में सामाजिक सरोकार की खबरें लगातार कम होती जा रही हैं। खबरों में सनसनी परीसना और टीवी चैनलों की दिशाहीन डिबेट की होड़ में प्रिंट मीडिया तथा विशेष रूप से हिन्दी पत्रकारिता को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ की बात न करना न्यायसंगत नहीं होगा। एक समय था, जब किसी भी समाचार पत्र में संपादकीय उस समाचार पत्र आधार माना जाता था परंतु जब से पत्रकारिता की बागडोर बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के मालिकों के हाथों में गई है, तब से पत्रकारिता धीरे-धीरे सामाजिक सरोकार से दूर होते हुए एक व्यवसाय बनने की ओर अग्रसर हो चुकी है। हिन्दी शब्द से ही अपनत्व का भाव झलकता है। हिन्दी हमारी मातृभाषा है मातृ अर्थात् माँ के समान। जिस प्रकार एक मनुष्य की भावनाएं माँ से जुड़ी होती है और माँ से अपना दुख व सुख सरल रूप से व्यक्त कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार हिन्दी के माध्यम से हम अपनी हर वो बात प्रतियेक भारतीय से साझा कर सकते हैं जो कदाचित किसी और भाषा में करना संभव न हो। हिन्दी पत्रकारिता का प्रारंभ भी देश, समाज और व्यक्तिविशेष की भावनाओं व अपेक्षाओं को साझा करने के लिए ही हुआ था।

हिन्दी पत्रकारिता दिवस प्रति वर्ष 30 मई को मनाया जाता है 30 मई 1826 को हिंदी भाषीय समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड "साप्ताहिक पंडित जगल किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ता से शुरू किया गया था और तब से इस तिथि को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में विदित किया जाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकार आज भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। पंडित जगल किशोर शुक्ल जी इस साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक व प्रकाशक स्वम ही थे, पंडित जी का हिंदी पत्रकारिता जगत में विशेष सम्मान है। पेशे से अधिवक्ता जगल किशोर जी मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे परन्तु उन्होंने उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में कलकत्ता को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना था। दूरअसल उन्होंने यह समाचार पत्र व्यवसाय की दुष्टि से नहीं अपितु तत्कालीन अंग्रेजी हकूमत के विरुद्ध, कलम का युद्ध आरम्भ किया



था। दुर्भाग्यवश इस समाचारपत्र की केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए और आर्थिक अभाव के चलते 1827 में यह समाचार पत्र बंद भी हो गया किंतु हिंदी पत्रकारिता को हथियार बनाकर स्वतंत्रता संग्राम का विगुल बज चुका था।

आज यदि हम हिन्दी पत्रकारिता के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं तो हमें यह भी अवश्य जानना चाहिए कि 1826 से लेकर 2023 तक के इस सफर में पत्रकारिता जगत और एक पत्रकार की कार्यशैली में क्या क्या परिवर्तन आया है। प्रारंभ से लेकर वर्तमान सफर की यात्रा के दृष्टिगत हिंदी पत्रकारिता का संघर्ष आज भी जारी है। स्वाधीनता की अपेक्षाओं के गर्भ से उत्पन्न हुई हिंदी पत्रकारिता आज अपेक्षाओं का शिकार होने लगी है और इसका मुख्य कारण मिशन से व्यवसाय में परिवर्तित होना है। निष्पक्ष पत्रकारिता अप्रत्यक्ष रूप से निजी स्वार्थों की पूर्ति के साधन बन चुका है। हिंदी पत्रकारिता का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तविक स्वरूप उजागर करने के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी है किंतु वर्तमान परिस्थितियों में पत्रकारिता व पत्रकार अपने मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं।

पत्रकारिता का यह स्वरूप दिल्ली से देहात तक की वर्तमान पत्रकारिता में देखा जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पत्रकारिता को हम व्यवसाय न बना कर एक विधा के रूप में सम्पूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करें। सूचना एकीकृत करना केवल मात्र पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है बल्कि समाज से पहले ज्ञान और विविध प्रकार की जानकारीयों हासिल करके समाज को शिक्षित करना और उचित मार्गनिर्देशन की विधा ही हिंदी पत्रकारिता का सही स्वरूप है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अशिक्षा, धार्मिक उन्माद, दंगा

फसाद, रिश्तवखोरी, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध मुखर होना हिन्दी पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। जिस दौरान हिंदी पत्रकारिता का उदय हुआ उस समय समाज में राष्ट्रीय चेतना की आवश्यकता थी समाज में देशप्रेम की भावना जागृत करने में पत्रकारिता का अतुल्य योगदान रहा है। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हिंदुस्तानियों के हित के हित उद्देश्य से हुई थी उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्तमान के परिदृश्य में भी हिंदी पत्रकारिता भीष्मपितामह की भूमिका निभा रही है।

आधुनिकता की प्रतिस्पर्धा के दौर में भी हिंदी पत्रकारिता स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम दिखाई दे रही है और यह हिंदी पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए गर्व की बात है। सर्वेक्षण के अनुसार देश में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के तुलनात्मक हिंदी समाचार पत्रों की पंजीकृत संख्या सबसे अधिक होना, हिन्दी पत्रकारिता की सफलता व सार्थकता का जीवंत प्रमाण माना जा सकता है परन्तु इसका अर्थ यह कहना नहीं है कि हिन्दी पत्रकारिता के अस्तित्व के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है अपितु हिंदी पत्रकारिता को और अधिक प्रखर व सशक्त बनाने के लिए पत्रकार जगत में कार्य कर रहे लोगों को आगे आना होगा।

हिन्दी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष में पत्रकार जगत से जुड़े महानुभावों को यह प्रण लेना होगा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता के उद्देश्य से हिन्दी पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ था, इसी प्रकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सच्चाई से ओतप्रोत, निर्भिक, निस्वार्थ भाव की पत्रकारिता करके स्वस्थ व खुदगु राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का सकारात्मक प्रयास करें तदुपरांत ही आज के दिवस अर्थात् हिंदी पत्रकारिता दिवस को सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

प्रार्थनाओं की जगह



स्वस्थ, सुंदर और निर्मल हो जाती हैं। अहंकार से इंसान को मुक्त कर विनम्रता और प्रेम से सराबोर कर देती हैं। प्रार्थनाएं वर्गों में विभाजित नहीं होतीं, समूची मनुष्य जाति के कल्याण के लिए होती हैं।

अगर हमारी प्रार्थनाएं करुणा, भाईचारा, प्रेम, सहिष्णुता उत्पन्न करने में विफल हो रही हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उनके वास्तविक रूप और उद्देश्य को स्वार्थपूर्ति के चलते बदल दिया गया है। अब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम किसी रणनीति का शिकार हो चुके हैं। प्रार्थना केवल आध्यात्मिक या धार्मिक शब्द ही नहीं है, यह आधिकारिक शब्द भी है। हम सभी को प्रार्थना पत्र लिखना शिक्षा के शुरुआती दौर में ही सिखा दिया गया था जो भविष्य को लेकर विद्यार्थियों को

सुनिश्चित करता है कि वे एक सभ्य समाज में हैं, जहां अगर प्रार्थना की शैली पत्र लिखा जाए, तो उस पर चिंतन किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है।

प्रार्थना केवल एक शब्द ही नहीं है, वह जीवन जीने का तरीका है। हम एक दूसरे को किस तरह से संबोधित करते हैं, यह जानकर कोई हमारे समाज का बुनियादी ढांचा, जैसे कि हमारी कार्यप्रणाली, शिष्टाचार, एकजुटता और भविष्य में हमारी प्रगति की संभावना के बारे में भी अनुमान लगा सकता है। प्रार्थना के पर्यायवाची शब्दों पर गौर करें, तो पाएंगे कि ये वही शब्द हैं, जिनके अर्थ उपयोग से हम अपनी बात को संयमित और संतुलित तरीके से दूसरे के

समक्ष प्रस्तुत कर रहे होते हैं। अनुरोध, निवेदन, विनती आदि ये शब्द सभ्य समाज के मालूम होते हैं। जहां निवेदन होता है, वहां यह उम्मीद भी होती है कि विचार-विमर्श और बेहतरी की संभावनाएं अभी बची हुई हैं। एक स्वस्थ प्रणाली मौजूद है, जिस पर हम अपने विचारों को इस विश्वसनीय के साथ साझा कर सकते हैं कि उन पर ईमानदारी से, बिना पूर्वाग्रह के, निष्पक्ष रूप से विमर्श किया जाएगा। स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की नींव इन्हीं शब्दों के होने से संभव का ही जा सकता है।

पारिवारिक आत्मीय संबंधों की बात हो या औपचारिक नौकरी पेशे से जुड़ी व्यवहार कुशलता की, प्रार्थनाओं का असर प्रभावपूर्ण रहा है। किसी भी काम को करवाने के मुख्य रूप से दो तरीके संभव हैं- या तो आदेश दिया जाए या फिर निवेदन किया जाए। आदेशात्मक शैली में अनिवार्यता का भाव रहता है, जो काम के हो जाने को लेकर हमें निश्चित कर देता है। वहीं अनुरोध का भाव ऐसा वातावरण निर्मित कर देता है, जहां काम के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपनेपन का भाव उत्पन्न होने लगता है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जब अपने काम में सम्मिलित हो जाता है, तब बार-बार निरीक्षण करने की जरूरत कम हो जाती है। इस तरह के वातावरण में मिले परिणाम में गुणवत्ता लगातार बनी रहती है, साथ ही व्यक्तिगत खुशी, आत्मसम्मान और संतुष्टि का भाव भी बना रहता है। ऐसे में संतुष्ट व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी बेहतर वातावरण देने की कोशिश करने लगता है, इस तरह से समाज और दुनिया धीरे-धीरे स्वस्थ और संपन्न होती चली जाती है। घर, मुहल्ले, शहरों, छोटे-छोटे समूहों से शुरू हुई यह प्रार्थनाएं मनुष्य के जीवन के लगभग हर पक्ष को छूती हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि हमारी प्रार्थनाएं अपने उद्देश्य से कभी भटक न जाएं। उम्मीदों और सामाजिक सरोकार से भरी प्रार्थनाओं को जीवन में हमेशा बने रहना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य: तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाला एक मूक संकट



रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से गंभीर वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया है कि देश में 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अवसाद विश्व स्तर पर 300 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है, और यह 2030 तक विकलांगता का प्रमुख कारण होने की भविष्यवाणी की जाती है।

2024 में, भारत में अध्ययन अवसाद एक महत्वपूर्ण बोझ को प्रकट करता है, अनुमान के साथ यह दर्शाता है कि 56 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं और अनुसंधान बढ़ते रूझान की ओर इशारा करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ जनसांख्यिकी के बीच।

तेजी से शहरीकरण, आर्थिक दबाव, सामाजिक अलगाव और महामारी जैसे कारकों ने वृद्धि में योगदान दिया है। भारत में द्विध्रुवी विकार परिदृश्य भी काफी गंभीर है, देश में 150 में से लगभग 1 व्यक्ति इससे पीड़ित है, और काफी परेशान है, 70 प्रतिशत अनुपचारित है।

यह कम मूड, कम ऊर्जा, ब्याज की हानि, नींद की समस्याओं, विचारों या आत्म-नुकसान के कृत्यों के साथ-साथ उन्माद के एपिसोड की विशेषता है। शोध अब इस तथ्य पर प्रकाश डाल रहा है कि आत्महत्या के लिए अपनी जान गंवाने वाले 60 प्रतिशत लोगों में अवसाद या द्विध्रुवी विकार जैसे मूड की बीमारी है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस सबसे दुखद अंतिम चरण से पहले प्रगति की एक श्रृंखला को और इशारा करता है।

जब हम भारत में मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य में गहराई से देखते हैं, तो कई मुद्दे जिनका मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है - सामने आते हैं।

जब हम भारत में मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य में गहराई से देखते हैं, तो कई मुद्दे जिनका मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है - सामने आते हैं। छात्रों और युवा के मामले में, कई भौतिक चीजों की खोज में बहुत व्यस्त हैं क्योंकि उनके लिए पूरी जगह बेहद प्रतिस्पर्धी हो गई है, विश्राम और उपन्यास पर ध्यान कम हो गया है, और परिणामस्वरूप जलने वाले बाहरी और अवसाद उनके जीवन को घेर लेते हैं।

इस सब में, इंटरनेट और सोशल मीडिया का दबाव बढ़ाने और अप्राप्य और अति महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को स्थापित करने में प्रभाव - सहकर्म दबाव के सौजन्य से, युवाओं के जीवन में भी कहर ढा रहा है।

बुजुर्गों के मामले में, हम अकेलेपन में वृद्धि देख रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे या तो पढ़ाई या नौकरी के कारण

उनके साथ नहीं रह रहे हैं, या व्यस्तता और अपने व्यस्त कार्यक्रम से अलग होने में असमर्थता के कारण बहुत कम समय बिता रहे हैं। इसलिए बढ़ती असुरक्षा के साथ-साथ बढ़ती उम्र का डर है - उम्र बढ़ने के कारण जब वे अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंचेंगे, तो उनकी देखभाल कौन करेगा।

महामारी के बाद से, हम नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर अधिक जोर दे रहे हैं। और उन्हे कई भौतिक मुद्दों के रूप में प्राथमिकता के रूप में माना जा रहा है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (टेली मानस) और आयुष्मान भारत, एचडब्ल्यूडी योजना सहित मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं।

टेली मानस एक टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मुफ्त, 24/7 मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है, जबकि आयुष्मान भारत योजना प्राथमिक स्वास्थ्य

आर्थिक आशंकाओं के बीच खेती



विजय गर्ग

पिछले दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में प्रमति की सराहना करते हुए कहा कि इससे दोनों देश लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि तेजी से आगे बढ़ रहे द्विपक्षीय कारोबारी समझौते में भारत द्वारा अमेरिका से कृषि आयात पर शुल्क कमी के प्रावधान भी हैं। भारत ने प्रारंभिक रूप से अमेरिका को बादाम, अखरोट, कैनबेरी, पिस्ता और दाल जैसे कृषि उत्पादों पर शुल्क कटौती पर सहमति के संकेत दिए हैं। इस समय अमेरिका में चीन के कई कृषि उत्पादों पर लागू 245 फीसद शुल्क की तुलना में १०।90 दिन बाद भारत के कृषि निर्यात पर लागू होने वाले 26 फीसद शुल्क का परिदृश्य अमेरिका में भारत के खाद्यान्न और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात के मौके बढ़ाने वाला है। चूंकि इस वर्ष वैश्विक खाद्यान्न व्यापार के घटने की रफ्तार आ रही है, ऐसे में कृषि उत्पादों का अधिक निर्यात भारत के लिए विदेशी मुद्रा की अधिक कमाई का माध्यम भी बन सकता है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि जिस तरह पांच साल पहले कोरोना से जंग में हमारे खाद्यान्न भंडार देश के हथियार बन गए थे, उसी प्रकार इस समय अमेरिकी शुल्क की मार के साथ-साथ शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि को कम करने के मद्देनजर देश में रिकार्ड पैदावार और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद एक मजबूत हथियार दिखाई दे रहे हैं। अगर हम वर्ष 2024-25 के लिए जारी मुख्य कृषि फसलों (खरीफ एवं रबी) की पैदावार के र दूसरे अनुमान की ओर देखा, की ओर देखें, तो पाते हैं चावल, गेहूँ, मक्का, मूंगफली एवं सोयाबीन के साथ-साथ तुअर और चने की भी रिकार्ड पैदावार की उम्मीद जताई गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि देश में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 33 करोड़ टन से भी अधिक होने का अनुमान है।

इसी तरह फल और सब्जी उत्पादन में भी तेज वृद्धि होगी। नहीं, वर्ष f 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद में (जीडीपी) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में 4.6 फीसद वृद्धि हो सकती है। पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 2.7 फीसद थी। अच्छा मानसून भी कृषि विकास को नई ऊंचाई दे सकेगा। पिछले दिनों मौसम विभाग ने इस साल देश में मानसून के दौरान औसत से पांच फीसद अधिक वर्षा का अनुमान जताया है। इससे ग्रामीण भारत सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और कृषि निर्यात भी बढ़ेगा।

निश्चित रूप से से देश में बढ़ता खाद्यान्न उत्पादन और मजबूत होती ग्रामीण आर्थिकी देश की आर्थिक शक्ति बन गई है। इस समय देश में खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं और अनाज निर्यात बढ़ रहा है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तवर्ष 2024-25 के दौरान शुल्क चुनौतियों और विश्व व्यापार को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच भारत के कृषि निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। देश का कुल कृषि निर्यात 50 अरब डालर के पार पहुंच गया है। भारत के कृषि क्षेत्र के निर्यात में हुई बढ़ोतरी का मुख्य कारण चावल के निर्यात में 20 फीसद की वृद्धि और बढ़ती रफ्तार से शुरू हुई यह प्रार्थनाएं मनुष्य के जीवन के लगभग हर पक्ष को छूती हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि हमारी प्रार्थनाएं अपने उद्देश्य से कभी भटक न जाएं। उम्मीदों और सामाजिक सरोकार से भरी प्रार्थनाओं को जीवन में हमेशा बने रहना चाहिए।

सेवा में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) भारत की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख घटक हैं। बुजुर्गों के लिए, सरकार ने बुजुर्गों (NPHC) और अटल वायो अयुध्दय योजना (AVYA) के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है।

एनपीएचसी वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। AVYA वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी पहलों का समर्थन करता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अनुदान-सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डरलाइन) मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे लोगों के लिए भावनात्मक समर्थन सहित समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है।

यह बेहद आवश्यक करने वाला है कि हमारे राष्ट्र का उच्चतम स्तर - स्थिति की गंभीरता के लिए जागरूक और जीवित है। वास्तव में, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अपने विचारों से संभावित समाधानों के साथ सामने से नेतृत्व किया है जो इस महत्वपूर्ण विषय को संबोधित करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। अपने लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' में, उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से वर्तमान युग में युवाओं के बीच, और शारीरिक

अरब डालर से अधिक हो गया है। एक दशक से भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन हुआ है।

इस तरह, जहां देश में खाद्यान्न की कमी से खाद्यान्न अधिशेष की ऊंचाइयां देश के लिए लाभप्रद बन गई हैं, वहीं भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी शुल्क संग्राम में भारत की आर्थिक ताकत बन गया है। वित्तवर्ष 2023-24 की तुलना में भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात वित्तवर्ष 2024-25 में 13 फीसद बढ़ कर 25.14 अरब डालर हो गया है। यह एक ऐसा उभरता उद्योग है, जिसमें पिछले दस वर्षों 1 वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) की खाद्य प्रसंस्करण पर प्रकाशित शोध अध्ययन रपट उल्लेखनीय है। इसके मुताबिक भारत के खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र वर्ष 2023 में 307 अरब डालर का था, यह तेजी से बढ़ कर वित्तवर्ष 2030 तक 700 अरब डालर, वर्ष 2035 तक 1100 अरब डालर, वर्ष 2040 तक 1500 अरब डालर और वर्ष 2047 तक 2150 अरब डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। रपट में कहा गया है कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से निर्यात लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2030 तक 125 अरब डालर, वर्ष 2035 तक 250 अरब डालर, वर्ष 2040 तक 450 अरब डालर और वर्ष 2047 तक 700 अरब डालर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा।

इस नए व्यापार युग में कृषि और ग्रामीण विकास के आधारों को और मजबूत बनाना 1 बनाना होगा। निश्चित रूप से अमेरिका की ओर से थोपे गए शुल्क से इस समय देश की आर्थिकी को होने वाले किसी भी नुकसान भरपाई के साथ भविष्य में भी अन्य किसी भी वैश्विक आर्थिक चुनौती का का मुकाबला करने के लिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभारने पर तेजी से काम करना होगा। इसमें कोई दो मत

कृषि के बुनियादी ढांचे और निवेश पर पिछले एक दशक में रणनीतिपूर्वक ध्यान दिए जाने के अच्छे परिणाम मिले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ने से ग्रामीण-शहरी दूरियों में कमी ला दी है। भारतीय किसान तेजी से डिजिटल भुगतान, फसल बीमा और बैंकों से औपचारिक ऋमा की सुविधाओं की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उम्मीद कि अमेरिका के साथ पारस्परिक उत्पादों भारत-अमेरिकी रू कारोबार पर शुल्क की कमी और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और कृषि निर्यात भी बढ़ेगा।

निश्चित रूप से से देश में बढ़ता खाद्यान्न उत्पादन और मजबूत होती ग्रामीण आर्थिकी देश की आर्थिक शक्ति बन गई है। इस समय देश में खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं और अनाज निर्यात बढ़ रहा है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तवर्ष 2024-25 के दौरान शुल्क चुनौतियों और विश्व व्यापार को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच भारत के कृषि निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। देश का कुल कृषि निर्यात 50 अरब डालर के पार पहुंच गया है। भारत के कृषि क्षेत्र के निर्यात में हुई बढ़ोतरी का मुख्य कारण चावल के निर्यात में 20 फीसद की वृद्धि और बढ़ती रफ्तार से शुरू हुई यह प्रार्थनाएं मनुष्य के जीवन के लगभग हर पक्ष को छूती हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि हमारी प्रार्थनाएं अपने उद्देश्य से कभी भटक न जाएं। उम्मीदों और सामाजिक सरोकार से भरी प्रार्थनाओं को जीवन में हमेशा बने रहना चाहिए।

भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अधिष्ठाता, संस्कृत-संस्कृति के संवर्धक आद्यगुरु शंकराचार्य

सुशील कुमार 'नवीन'

भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अधिष्ठाता, संस्कृत और संस्कृति के संवर्धक राष्ट्रभक्त आद्यगुरु शंकराचार्य की शुरुआत दो मई को जयंती है। उनका जन्म 788 ईस्वी में वैशाख माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा को प्रदर्शित कर दिया था। आठ वर्ष की उम्र में ही वे वेदों के ज्ञान में पारंगत हो चुके थे। संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा कर चारों दिशाओं में चार पीठों की स्थापना की। ये पीठ गोवर्धनपुरी (जगन्नाथपुरी), श्रंगेरी (रामेश्वरम्), शारदा (द्वारिका) और ज्योतिर्मठ (बद्रीनाथ धाम) के नाम से हम सब जानते हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन को स्थापित करने के साथ-साथ संस्कृत भाषा और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।

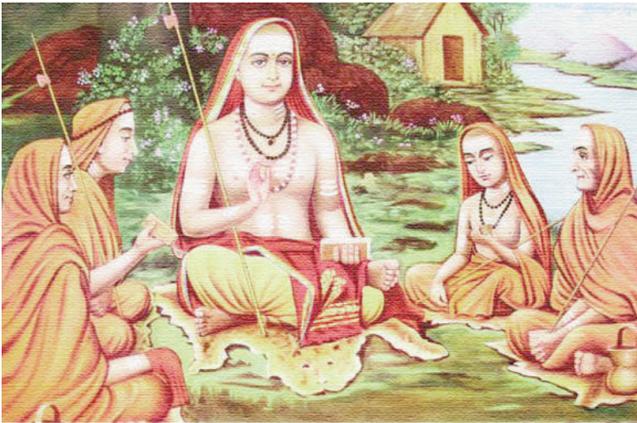
इनका जन्म स्थान केरल माना जाता है। पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। उनका मूल नाम शंकर था, लेकिन उन्हें श्रीशंकराचार्य के रूप में प्रसिद्धि मिली। पांच वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार करवाकर कर उन्हें विद्याध्ययन हेतु भेजा गया। दो वर्ष में ही षडंग सहित वेदों का अध्ययन पूर्ण कर वे घर वापस आ गये। उसी समय उनके अंदर संन्यास लेने की इच्छा प्रबल हो उठी थी, पर माता ने उन्हें इसके लिए स्पष्ट

सांस्कृतिक पुनर्जागरण अग्रणी, संस्कृत-संस्कृति के संवर्धक आद्यगुरु शंकराचार्य

रूप से इनकार कर दिया। शंकर मातृभक्त थे, इसलिए उनकी अनुमति के बिना वे संन्यास नहीं लेना चाहते थे। वो कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा गया है वो सही समय पर होकर रहता है। जिस संन्यास के लिए शंकर की माता का स्पष्ट इनकार था, परिस्थिति ऐसी बनी कि उन्हें उसके लिए शंकर को अनुमति देनी पड़ी।

बताते हैं कि एक दिन वे माता के साथ नदी तट पर गये, वहां स्नान करते समय एक ग्राह (मगरमच्छ) ने उनका पैर पकड़ लिया। वह उन्हें पानी में अंदर की तरफ खींचने लगा। ऐसी स्थिति में उनकी माता सहायता के लिये चिल्लाने लगीं। उसी समय उन्होंने माता से कहा 'यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दें तो यह ग्राह मुझे छोड़ देगा।' पुत्र मोह में माता ने फौरन हां कर दी। विधि का विधान देखिए माता के संन्यास की हामी भरते ही ग्राह ने उनका पैर छोड़ दिया। माता से अनुमति लेकर उन्होंने आठ वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया।

गृह त्यागने के बाद वे नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्वामी गोविन्द भगवत्पाद के आश्रम में पहुँचे और उनसे दीक्षा ग्रहण की। बहुत कम समय में ही



उन्होंने गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त लिया। इनकी योग्यता से खुश होकर गुरु ने उन्हें काशी जाने एवं वेदान्त सूत्र पर भाष्य लिखने की आज्ञा दी। काशी आने पर उनकी ख्याति सर्वत्र फैलने लगी। लोग इनका शिष्यत्व ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम

शिष्य सनन्दन हुए, जो पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए।

बाल्यकाल से ही असाधारण विद्वता को प्राप्त करने वाले शंकर ने भारतीय दर्शन और वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन किया। खासकर



अद्वैत वेदांत पर उनका विशेष ध्यान रहा। उन्होंने अपने जीवन के दौरान भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण कर विविध धार्मिक वाद-विवादों में हिस्सा लिया। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों की व्याख्या की और अनेक शास्त्रीय ग्रन्थों की टीका तथा व्याख्या की। भारतीय साहित्य और धार्मिक संस्कृति को एक मजबूत आधार प्रदान करने में उनका योगदान

सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके विचार और सिद्धांतों ने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा पर अत्यंत प्रभाव डाला। उनके द्वारा स्थापित वेदांत के सिद्धांत आज भी विश्वसनीय और महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

उनके द्वारा स्थापित अद्वैत वेदान्त के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को एकता और एकात्मता की दिशा में अग्रसर किया। उनके अनुसार जगत में अनंतता की दिशा में सत्य एक है और सभी जीवों में एक ही आत्मा का आभास होता है। उन्होंने समाज में धार्मिक समरसता और सहयोग को प्रोत्साहित करने के साथ धर्म, भाषा, और क्षेत्रीय भेदों को दूर करने का भी संदेश दिया। वे सभी भारतीयों को एक सामान्य आधार पर जोड़कर राष्ट्रीय एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक और जातिवादी भेदों का खंडन करने में भी वे पीछे नहीं रहे। उनका मुख्य सिद्धांत था कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और आत्मा ब्रह्म है। उनके द्वारा शिक्षित अनुयायियों ने भी भारतीय समाज में समरसता, सामंजस्य, और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। उनके विचार और संदेश राष्ट्रीय एकता और समरसता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित दार्शनिक सिद्धांतों ने भारतीय समाज में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की भावना को

आईना और अतीत: जब पहचान डीएनए से झाँकती है

[जीन में बसी स्मृतियाँ: हमारे भीतर साँस लेता इतिहास]



कभी रात की गहरी खामोशी में एक अनजानी धुन आपके दिल को धाम लेती है? कोई पुरानी गंध, कोई धुंधली सी छवि, या किसी पत्थर का टंडा स्पर्श आपको अचानक ऐसी स्मृतियों में खींच ले जाता है, जो आपके नहीं, बल्कि हमारे जुदा नहीं। जैसे कोई अनदेखा रिश्ता, कोई सदियों पुराना बंधन आपके जीन में साँस ले रहा हो। यह कोई खयाल नहीं, कोई संयोग नहीं — यह आपके डीएनए का वह अमर गीत है, जो हजारों सालों से गूँज रहा है। आपके खून में, आपके हर कोशिका में, एक ऐसा इतिहास लिखा है, जो न सिर्फ आपके पूर्वजों का है, बल्कि आपके होने की वजह है। तो चलिए, एक ऐसी यात्रा पर, जो न सिर्फ रोमांच से भरी है, बल्कि हमें हमारे वजूद की गहराइयों में ले जाती है — वहाँ, जहाँ हम सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक जीवंत महाकाव्य हैं।

हम इतिहास को किताबों की धूल भरी पन्नों में, टूटी-फूटी मूर्तियों में, या पुराने किल्लों की दीवारों पर खोजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सबसे सच्चा, सबसे जिंदा इतिहास आपके भीतर धड़क रहा है? आपके खून का हर कतार सिर्फ जिंदागी नहीं ढोता — वह सदियों के प्रेम, संघर्ष, हँसी, और आँसुओं का खजाना है। यह खून किसी राजा का हो सकता है, जो सोने के तख्त पर बैठकर दुनिया जीतने के सपने देखता था। यह किसी जंगल के शिकारी का हो सकता है, जो चाँदनी रात में तीर साधता था। यह किसी रेशमी साड़ी में लिपटी रानी का हो सकता है, या किसी किसान का,

जिसने सूरज की तपिश में खेतों को अपने पसीने से सींचा। विज्ञान इसे रजनीतिक इन्हेरिटेन्स का नाम देता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है — यह एक ऐसी कहानी है, जो आपके जीन में लिखी है, और हर पल आपके जरिए जी रही है।

आज की जेनेटिक्स ने एक चौंका देने वाला राज खोला है: हमारी भावनाएँ, हमारी आदतें, यहाँ तक कि हमारे डर भी, हमारे पूर्वजों की देन हैं। इसे एपीजेनेटिक मेमोरी कहते हैं — स्मृतियाँ, जो दिमाग में नहीं, बल्कि जीन में बसी होती हैं। शोध बताते हैं कि हमारे पुरुषों ने जो दर्द, जो आघात झेले — युद्ध की त्रासदी, भूखमरी की पीड़ा, या उत्पीड़न का जख्म — वे जीन के जरिए हम तक पहुँचते हैं। 2018 में नेचर जर्नल में छपा एक अध्ययन कहता है कि तनाव झेलने वाले चूहों के बच्चों में बिना किसी कारण चिंता के लक्षण दिखे। इंसानों पर हुए शोध, जैसे हॉलैंड के हंगर विंटर (1944-45) के अध्ययन, बताते हैं कि भूखमरी से गुजरने वाली माताओं के बच्चों में मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ा। लेकिन यह सिर्फ शरीर की बात नहीं — यह भावनाओं की विरासत है। अगर आपके परनाना ने किसी युद्ध में अपने प्रियजनों को खोया, तो उस दर्द की हल्की सी गूँज आज भी आपके भीतर कहीं जिंदा है। यह विचार दिल दहलाने वाला है या रोमांच से भरा? शायद दोनों। क्योंकि इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपने नहीं — हम अपने भीतर अनगिनत अनजाने चेहरों की स्मृतियों का खजाना लिए घूमते हैं। कभी बेवजह का डर, किसी

रंग या सुगंध से अनजाना लगाव, किसी आवाज से बेचैनी — ये सब उस गुजरने जमाने के चिन्ह हो सकते हैं, जो हमारे जीन में अब भी साँस लेते हैं। जब आप किसी अनजानी जमीन पर खड़े होकर महसूस करते हैं, रमें यहाँ पहले आ चुका हूँ, र तो शायद यह आपका डीएनए है, जो आपको आपके पूर्वजों की की जमीन से जोड़ रहा है।

हम इतिहास को पुरानी किताबों और टूटी कन्नो में तलाशते हैं, मगर सबसे प्राचीन कथा तो हमारे जीन की कोशिकाओं में साँस लेती है। जब कोई बच्चा बिना सिखाए अनोखा हुनर दिखाता है, और माँ-बाप मुस्कराते हुए कहते हैं, र ये तो दादाजी पर गया है, र — वे अनजाने में उस वंशानुगत स्मृति को आवाज दे रहे होते हैं। यह स्मृति सिर्फ गुणों की नहीं, भावनाओं की भी गवाह है। विज्ञान खुलासा करता है कि जिनके पूर्वज भूखमरी, गुलामी, या युद्ध जैसे कष्टों से गुजरे, उनके वंशजों में बिना कारण चिंता या भविष्य की आशंका ज्यादा देखी जाती है। यह जीन का वह गुप्त कोड है, जो सदियों पुराने दर्द को आज भी जीवित रखता है। जब कोई कहता है, र मैं अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता हूँ, र तो वह महज सांस्कृतिक यात्रा पर नहीं निकलता — वह अपने डीएनए की रहस्यमयी गहराइयों में गोता लगाता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में लोग डीएनए टेस्ट के जरिए अपनी उत्पत्ति का सच खोज रहे हैं। यह खोज सिर्फ जगहों की नहीं, हमारे वजूद की है। हम कौन हैं? यह सवाल अब केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि विज्ञान की चौखट पर भी दस्तक देता है।

अगर एक दिन आपको पता चले कि आपके जीन में किसी अनजान मुल्क, संस्कृति, या समुदाय की रहस्यमयी छाप छिपी है, तो क्या होगा? क्या आप वही रहेंगे, जो आज हैं? या शायद हमारी पहचान कोई स्थिर चित्र नहीं, बल्कि एक जीवंत नदी है — सदियों से हमें चुकती, मिटाती, और नए रंगों में रंगती हुई। डीएनए युद्ध के खुलासा करता है कि मानव इतिहास कोई खंडित कहानियों का पुलिंदा नहीं — न जातियों का, न रंगों का, न सरहदों का। यह एक विशाल समंदर है, जिसमें हम सब एक बूँद हैं। और हर बूँद में उस अनंत समुद्र का पूरा नक्शा समाया है। अगली बार जब आप आइने में खुद को देखें, तो रुकिए और सिर्फ अपनी आँखों को न निहारें। उनके पीछे की गहराई में झाँकें। वहाँ, शायद कोई अनजाना चेहरा आपको देखकर स्मरकुरा रहा हो — कोई ऐसा, जिसकी आप कभी नहीं मिले, फिर भी जिसके कारण आप आज यहाँ साँस ले रहे हैं। हमारा शरीर भले ही क्षणभंगुर हो, लेकिन हमारे जीन में बस्ता इतिहास — वह अनंत और अमर है।

— प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़दानी (मप्र)

मजदूर दिवस: एक दिन सम्मान, साल भर अपमान

मजदूर दिवस केवल एक तारीख नहीं, श्रमिकों की मेहनत, संघर्ष और हक की पहचान है। 1 मई को मनाया जाने वाला यह दिन उस आंदोलन की याद है जिसने काम के सीमित घंटे, सम्मानजनक वेतन और श्रम अधिकारों की लड़ाई लड़ी। लेकिन भारत जैसे देशों में मजदूर आज भी असंगठित, असुरक्षित और उपेक्षित हैं। महिला श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय है। एक दिन की प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि से आगे बढ़कर हमें हर दिन श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षा और व्यापक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। तभी मजदूर दिवस वास्तव में सार्थक होगा

— प्रियंका सौरभ

हर वर्ष 1 मई को मनाया जाने वाला मजदूर दिवस, श्रमिकों के संघर्ष, बलिदान और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि समाज की नींव उन हाथों से बनती है जो दिन-रात मेहनत करते हैं। लेकिन क्या हम सच में इन मेहनतकशों को वह सम्मान और अधिकार देते हैं, जिसके वे हकदार हैं? क्या यह सिर्फ एक दिन का प्रतीक बनकर रह गया है या फिर इसका सार्थकता का कार्य पूरे वर्ष में होना चाहिए?

मजदूर दिवस की शुरुआत 1886 में मेन्सिंगो, अमेरिका से हुई थी। उस समय श्रमिकों ने 8 घंटे काम के दिन की मांग को लेकर आंदोलन किया। इस संघर्ष में कई श्रमिकों की जान गई, और यह घटना 'हेमकेट कांड' के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद, 1889 में पेरिस में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। भारत में, यह दिन पहली बार 1923 में मद्रास (अब चेन्नई) में मनाया गया। तब से लेकर आज तक, मजदूर दिवस श्रमिकों के अधिकारों और उनके संघर्ष की याद दिलाने का दिन बन चुका है।

भारत में श्रमिकों की स्थिति अब भी चिंताजनक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, भारत में बेरोजगारी की दर अप्रैल 2024 में बढ़कर 8.1 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, भारत में लगभग 43 करोड़ लोग दिहाड़ी मजदूर या कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जो असुरक्षित और अनौपचारिक श्रमिक माने जाते हैं। यह असुरक्षा उनके जीवन को एक कठिन संघर्ष बना देती है, क्योंकि वे किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा या भविष्य की गारंटी के बिना काम करते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मजदूरों की औसत मासिक कमाई 10,000 से 20,000 रुपये के बीच है, जो अमेरिकी मजदूरों की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और स्थिर रोजगार की कमी है। विशेष रूप से महिला श्रमिकों को समान वेतन, मातृत्व अवकाश और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भारत में लाखों श्रमिकों का पंजीकरण नहीं होता, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। अगर श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए, तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकता है। इससे सरकार को श्रमिकों की सही संख्या का भी पता चलेगा और उनके लिए योजनाओं का संचालन और भी बेहतर हो सकेगा। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य योजनाएँ शामिल हो सकती हैं। यदि

श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ मिलता है, तो उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आ सकती है।

श्रमिकों को कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएँ, ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर मिलें, जिससे उनका रोजगार और जीवनस्तर बेहतर हो सके।

महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और समान वेतन की गारंटी दी जाए। इसके लिए विशेष कानूनों और प्रोटोकॉल का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे महिला श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हो सके। श्रमिकों के लिए प्रभावी कानूनों का निर्माण और उनके अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए। अगर श्रमिकों को उनका कानूनी संरक्षण सही तरीके से मिलता है, तो वे अपने अधिकारों का पालन करवा सकते हैं और बेहतर कार्य परिस्थितियों में काम कर सकते हैं।

भारत में श्रमिक आंदोलनों का इतिहास लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी श्रमिकों ने अपनी आवाज उठाई थी। हालाँकि, आजादी के बाद भी श्रमिकों की हालत में ज्यादा सुधार नहीं आया। श्रमिक आंदोलनों ने कई बार सरकारों को जागरूक किया है और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फिर भी, श्रमिकों की असुरक्षा और अधिकारों की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।

भारत में प्रमुख श्रमिक आंदोलनों में मजदूरों की असुरक्षा, वेतन, और श्रमिक अधिकारों के लिए आंदोलन होते रहे हैं। उदाहरण के लिए, 1970 के दशक में मुंबई के 'गेट वे ऑफ इंडिया' पर हुए श्रमिक आंदोलन ने मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई थी। वहीं, 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला लिया गया, तो उस समय भी श्रमिकों के अधिकारों के खिलाफ कई विवादास्पद घटनाएँ हुईं।

मजदूर दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक निरंतर संघर्ष का प्रतीक बनना चाहिए। यह दिन श्रमिकों के संघर्ष, बलिदान और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। अगर हम वास्तव में मजदूरों के योगदान का सम्मान करना चाहते हैं, तो हमें उनके अधिकारों का पालन करना होगा, उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन करना होगा और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। श्रमिकों को उनका हक मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, और उनका जीवन बेहतर बने। तभी हम सच्चे अर्थों में मजदूर दिवस को सार्थक बना सकते हैं।

इसलिए, हमें सिर्फ एक दिन मजदूरों को सम्मानित करने से ज्यादा, उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा। यही मजदूर दिवस का असली उद्देश्य है, और यह हमारी जिम्मेदारी भी है।

प्रेस का स्वतंत्र, निडर और पारदर्शी होना आवश्यक है (3 मई अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस विशेष आलेख)

सुनील कुमार महला

प्रत्येक वर्ष 3 मई को अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र में प्रेस का बहुत महत्व है। जैसा कि प्रेस के बारे में यह कहा गया है कि 'प्रेस की स्वतंत्रता के बिना न तो लोकतंत्र है, न पारदर्शिता है और न ही न्याय है।' प्रेस की स्वतंत्रता किसी देश के नागरिकों को सरकार और अन्य संस्थानों के काठको निगलने का करने में मदद करती है, जिससे वे सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और जागरूक बन सकते हैं। यहाँ पाठकों को बताता चलूँ कि वाल्टर क्रोनकाइट ने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में यह बात कही है कि 'प्रेस की स्वतंत्रता न केवल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वयं लोकतंत्र है।' वास्तव में, यह (3 मई का दिन) पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक सूचनापरक चर्चा के लिए 'स्वतंत्र प्रेस' के महत्व को रेखांकित करने का दिन है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के 'जन सूचना विभाग' ने मिलकर इस दिन को मनाने का निर्णय किया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' ने भी '3 मई' को 'अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस' की घोषणा की थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में वर्ष 1993 में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। सच तो यह है कि 1993 से हर साल 3 मई को मनाया जाने वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक महत्व और लोकतंत्र, पारदर्शिता और मानवाधिकारों की रक्षा में पत्रकारिता की भूमिका की याद दिलाता है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि नामीबिया में वर्ष 1991 में अपनाई गई 'विंडहोक घोषणा' में मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस का आह्वान किया गया था। उपलब्ध को बताता चलूँ कि 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' 2025 का आधिकारिक विषय/थीम 'बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग - प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कुत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव' रखा गया है। वास्तव में यह थीम इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे उपरती हुई तकनीक, खास तौर

पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), पत्रकारिता को नया आकार दे रही हैं, सूचना तक पहुँच को प्रभावित कर रही हैं और प्रेस की आजादी के लिए ई-चुनौतियाँ पैदा कर रही हैं। सच तो यह है कि यह तेजी से विकसित हो रहे 'डिजिटल परिदृश्य' में पत्रकारिता की अखंडता की रक्षा करने की जरूरत पर जोर देता है। वास्तव में, इस दिन के मनाने का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों की गंभीरता के बारे में जानकारी देना है। यहाँ पाठकों को बताता चलूँ कि हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 की थीम 'प्रेस की बदलती प्रकृति' रखी गई थी। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि प्रेस हमेशा स्वतंत्र और जिम्मेदार होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रेस ही है जो जहाँ एक ओर जनमत को आकार देती है, सूचनाओं का प्रसार करती है, सरकार और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, तथा जनता को शिक्षित व जागरूक करने में मदद करती है। वास्तव में प्रेस लोकतंत्र की सच्ची प्रहरी और वाच डोग की भूमिका निभाती है। प्रेस ही किसी समाज और देश में विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देती है जिससे देश और समाज को उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में मदद मिलती है। वास्तव में सूचनाओं के प्रसार का यह (प्रेस) सबसे बड़ा उपकरण है। कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रक्षा करने और एक पारदर्शी, सशक्त एवं जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। आज प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ राजनीतिक संकल्पों के साथ ही न्यायिक दृढ़ संकल्प भी बहुत आवश्यक है। वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि वह विभिन्न पत्रकारों और मीडिया संगठनों को संसर्गित या सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की अनुमति दे। यदि हम यहाँ पर प्रेस की संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रेस का अलग है कि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता

भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। वास्तव में देश के सभी नागरिकों को बिना किसी रोक-टोक के अपनी बात रखने, विचारों और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। हालाँकि, इसकी कुछ सीमाएँ हैं जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता। सरल शब्दों में कहें तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है कि समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, वेबसाइटें और अन्य मीडिया संगठन अपनी राय, विचार और जानकारी को बिना किसी सरकारी या निजी संसर्गित प्रेस के प्रकाशित कर सकते हैं। बहरहाल, कहना चाहूँगा कि एक स्वतंत्र प्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और जानने के अधिकार सहित मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। यह व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों का पक्षधर बन कर इन अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। वास्तव में स्वतंत्र प्रेस के बहुत से महत्व हैं। मसलन यह लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। सूचनाओं का प्रसार करती है, विशेषकर उन सूचनाओं को जो छिपाई जा रही हों या जिनको समाज और देश से छिपाने का किसी द्वारा प्रयास किया जा रहा हो। अल्बर्ट कैमस ने 'प्रेस की स्वतंत्रता' को लेकर यह कहा है कि 'स्वतंत्र प्रेस अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन स्वतंत्रता के बिना यह कभी भी बुरा नहीं होगा।' बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वतंत्र प्रेस सरकार और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। यह भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन और अन्य गलत कृत्यों को उजागर करने में भी मदद करती है। वास्तव में एक स्वतंत्र प्रेस विविध विचारों और दृष्टिकोणों को एक सशक्त मंच प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक स्वतंत्र प्रेस विविध आवाजों एवं दृष्टिकोणों के लिये मंच प्रदान करता है, जिससे सुनिश्चित



होता है कि विभिन्न समुदायों की चिंताओं को सुना जा रहा है। यह (एक स्वतंत्र प्रेस) मानवाधिकारों की रक्षा करने में भी अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। पाठकों को बताता चलूँ कि हमारे देश में भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए), एडिटेडर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो कि भारत के प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं के संपादकों का एक स्वैच्छिक संघ है, भारत की विधिक प्रणाली (न्यायपालिका सहित) तथा रिपोर्टिंग विदाउट बॉर्डर्स और कमैटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थान हैं। आज भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबद्ध अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। मसलन, आज हमारे देश में भ्रष्टाचार, संगठित अपराध या सांघातिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने में

पत्रकारों को अनेक प्रकार की धमकियों और हिंसा (यहाँ तक कि हत्या) तक का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों और मीडिया संगठनों को प्रायः मानहानि के मुकदमों का भी सामना करना पड़ता है। आज मीडिया का स्वामित्व कुछेक शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के हाथ में है और इसके कारण संपादकीय निर्णय और नीतियाँ प्रभावित हो सकती हैं, आवाजों की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है। सरकारी विभिन्न मीडिया संगठनों को पुरस्कृत या दंडित करने के लिये विज्ञापन बजट का उपयोग एक साधन के रूप में कर सकती हैं, जो फिर उनकी रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकता है। राजद्रोह कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं। सेल्फ-सेंसरशिप भी मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। अतः आज भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस सुनिश्चित करने के लिये जरूरत इस बात की है कि मानहानि और राजद्रोह कानून जैसे कुछ कानूनों में सुधार किया जाना चाहिये। आज प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत बार सर्रे आम उल्लंघन होता है, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़े मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए और सख्त कार्रवाई हो। प्रेस सरकारी नियंत्रण और किसी भी राजनीतिक प्रभाव से सदैव मुक्त होनी चाहिए। पत्रकारों को उत्पीड़न, हिंसा और धमकियों से बचाया जाना बहुत आवश्यक और जरूरी है। सच तो यह है आज दर्शन और आधुनिकता का सामना कर रहे पत्रकारों को सम्मान देने की आवश्यकता है। मीडिया स्वामित्व पूर्णतया पारदर्शी होना चाहिए। इतना ही नहीं, सार्वजनिक प्रसारण की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। पत्रकारिता नैतिक मूल्यों, निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाली और निडरतापूर्वक होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी बहुत जरूरी और आवश्यक है। अंत में, फिनले पीटर डन के शब्दों में यही कहूँगा कि 'पत्रकारिता का कर्तव्य पीड़ितों को सांत्वना देना और सुविधा संपन्न लोगों को कष्ट देना है।'

“नेताओं की देशभक्ति की अग्निपरीक्षा, सेना में बेटा भेजो, पेंशन लो!”

भारत में एक बार विधायक या सांसद बन जाना आजीवन पेंशन की गारंटी बन चुका है, चाहे उनका संसदीय रिकॉर्ड शून्य क्यों न हो। वहीं, सीमाओं पर तैनात सैनिक हर रोज जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन उनके परिवारों को न्यूनतम सुविधाएं भी संघर्ष से मिलती हैं। सवाल उठता है — क्या नेताओं की देशभक्ति सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित है? क्यों नहीं उनके बेटे-बेटियां सेना में भर्ती होते? अगर आम जनता अपने बच्चों को देश सेवा के लिए भेज सकती है, तो नेता सिर्फ 'वोट' नहीं, 'बलिदान' भी दें। वक्त आ गया है कि नेताओं की पेंशन को सेना सेवा से जोड़ा जाए — ताकि देशभक्ति सिर्फ मंच की बातें न रह जाए, बल्कि जीने का सच्चा प्रमाण बने।

— डॉ. सत्यवान सौरभ



“पेंशन नहीं, पराक्रम दो: नेताओं की देशभक्ति का असली टेस्ट”
देशभक्ति का जोर जब चुनावी भाषणों में सिर चढ़कर बोलने लगे और हर गली-चौराहे पर तिरंगे का रंग दिखने लगे, तब हमें थोड़ा रुककर यह सोचना चाहिए कि यह प्रेम किसके लिए है — देश के लिए या कुर्सी के लिए? क्योंकि जिनके मुँह में हर पल 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' है, उनके बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, और कभी गलती से भी सीमा की तरफ नहीं देखते। लेकिन वही नेता, जब जनता से त्याग और बलिदान माँगते हैं, तो आत्मा काँप जाती है।

भारत में एक बार विधायक या सांसद बन जाने का मतलब है — रटियापट्टे में सेट है भाई! हर एक बार कुर्सी मिली, तो ज़िंदगी भर पेंशन, बंगला, सुरक्षा, गाड़ी, ड्राइवर, और 'माननीय' की उपाधि मुफ्त में। चाहे संसद में आपने एक भी सवाल न पूछा हो, चाहे सदन की कार्यवाही में सिर्फ झपकी ली हो, चाहे जनता आपको अगले चुनाव में बाहर का रास्ता दिखा दे — पेंशन

मिलती ही मिलती है!

क्या आपने कभी सुना कि एक सैनिक, जो सियाचिन में तैनात था और तीन साल में घर आया, उसे जीवन भर की पेंशन मिल गई हो? नहीं ना? उसे हर सेवा वर्ष का हिसाब देना पड़ता है। उसे शहीद होने पर भी 'मुआवजे' की फाइलें घूमती हैं।
देशभक्ति की बात करते समय नेता अक्सर कहते हैं — रहम तो देश के लिए जान देने को तैयार है! हर पर यह 'हम' कौन है? उनके बच्चे कहाँ हैं? क्यों नहीं कोई 'माननीय पुत्र' सीमा पर तैनात है? क्यों नहीं कोई 'राजकुमारी' मेडिकल कोर में है? सच्चाई यह है कि ये नेता देशभक्ति को अपनी राजनीतिक दुकान के प्रमोशनल पोस्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और उनके बच्चे उस दुकान से मुनाफा उठाते हैं।

अगर देश में जनता को मुफ्त राशन के लिए आधार-OTP देना पड़ता है, तो नेता की पेंशन के लिए भी एक शर्त होनी चाहिए — 'पेंशन तभी मिलेगी, जब आपके परिवार का कोई सदस्य सेना में सेवा देगा।'

कल्पना कीजिए क्या दृश्य होगा: एक विधायक के बेटे की युनिफॉर्म की पहली प्रेस हो रही है, एक सांसद की बेटे बूट पहन रही है, एक मंत्री का पोता हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है। क्या तब उनके बचानों में सच्ची देशभक्ति नहीं दिखेगी?

देश की सबसे कठिन सेवा — सेना की सेवा — को गरीब, मध्यम वर्ग के बच्चे निभाते हैं। जो जिनके पास न जुगाड़ है, न सुरक्षा। जो भर्ती में दौड़ते हैं, दौड़ते हुए मर भी जाते हैं। कोई कैमरा नहीं आता, कोई चैनल ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखाता। दूसरी ओर नेता के बच्चे अगर विदेश में शराब पीते पकड़े जाएं, तो भी नेता कहता है — रबेटा थोड़ा भटक गया, अब अमेरिका भेज रहे हैं पढ़ने के भाई, अगर 'भटकने' की सजा विदेश है, तो 'सीधे' लोगों को सजा क्यों?

हर बार चुनाव के समय सेना की तस्वीरें, सैनिकों की कहानियाँ, शौर्य गथाएँ पोस्टरों पर होती हैं। सजिकल स्ट्राइक का श्रेय लेने में हर दल आगे है, लेकिन उस ऑपरेशन में जान गंवाने वाले सैनिक का नाम किसी को याद नहीं। नेताओं

को सेना सिर्फ इमोशनल वोट बैंक लगती है — जब जरूरत हो, तो उनकी वर्दी का इस्तेमाल करो, जब चुनाव जीत जाओ, तो उनका हाल पूछना भी गुनाह मानो।

अगर सच में ये देशभक्ति दिल से है, तो नेताओं को पेंशन की जगह एक प्रमाण पत्र देना चाहिए कि उनके परिवार से कोई सदस्य सेना में सेवा दे रहा है या दे चुका है। ये एक नया कानून होना चाहिए — सिर्फ पेंशन के हक के लिए नहीं, बल्कि असली देशप्रेम का सबूत देने के लिए।

एक बार एक नेता जी भाषण दे रहे थे — 'अगर पाकिस्तान आँख उठाएगा, तो हम आँख निकाल लेंगे!'

एक नौजवान खड़ा हुआ और बोला — 'आपका बेटा कौन-सी यूनिट में है साहब?'

नेता जी मुस्कराए — 'वो तो इंजीनियरिंग कर रहा है, विदेश जाना है उसे...'

जनता हँसी नहीं, रोई। क्योंकि देशभक्ति अब सिर्फ 'नारा' बन गई है, 'नियति' नहीं।

देशभक्ति अगर सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाए, तो वह 'वोटबैंक की दुकान' बन जाती है। जब तक नेता और उनका परिवार उस देशभक्ति को जीते नहीं, तब तक हमें उनके भाषणों पर तालियाँ नहीं, सवाल उठाने चाहिए। नेताओं को पेंशन से ज्यादा जिम्मेदारी चाहिए, और उनके बच्चों को भाषण से ज्यादा बूट। देश को सिर्फ जनता नहीं, नेता भी बराबर दें — त्याग, परिश्रम और बलिदान।

देशभक्ति भाषणों से नहीं, भागीदारी से साबित होती है।

जब तक नेताओं के बच्चे सेना की वर्दी नहीं पहनते, तब तक उनके 'बलिदान' के बोल खोलके लगते हैं। पेंशन कोई सम्मान नहीं, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए — जो तभी मिले, जब परिवार भी राष्ट्र सेवा में उतरे। आम नागरिक के टैक्स पर ऐश करना बंद हो, अब बारी है नेता भी हिस्सा ले — सरहद पर, जमीन पर, और जिम्मेदारी में। वहाँ जनता सिर्फ सुनती रहेगी, और देश सेवा का बोझ उठाते रहेंगे वही, जिनके पास न ताकत है, न पहचान — सिर्फ जुनून है।

बालासोर पुलिस की नाकाबंदी और चेकिंग तेज, 10 जगहों पर चेकिंग के लिए तैनात



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूवनेश्वर : पहलगा आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट। विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में जांच और नाकाबंदी जारी है। खुफिया विभाग से मिले अलर्ट के बाद बालासोर पुलिस ने 10 स्थानों पर जांच चौकियाँ स्थापित की हैं। बालासोर में राज्य सीमा और जिला सीमा के बीच 10 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। विशेष रूप से उदयपुर में परिचम बंगाल की सीमा

से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के लक्ष्मणनाथ और भोगराई बॉर्डर पर कड़ी जांच की जा रही है। परिचम बंगाल जाने वाले सभी वाहनों की गहन जांच की जा रही है। इसी प्रकार, जिले के सभी मरीन पुलिस स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस तटीय क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और समुद्री नौकाओं पर नजर रखी रही है। जलमार्गों पर कासाफला और तलासरी समुद्री पुलिस स्टेशनों द्वारा गश्त की जा रही है।

मई दिवस: समस्याओं से ग्रस्त, खुशियों से दूर आज भी मजदूर

सुनील बाजपेई

कानपुर। हर साल की तरह इस बार भी एक मई यानी मजदूर दिवस मनाया गया। रैलियों निकल गईं। सभाएँ हुईं। समस्याओं के खिलाफ संघों का ऐलान किया गया। ठीक सब कुछ वैसा ही जैसा मई यानी मजदूर दिवस पर हर साल किया जाता है। और शायद भविष्य में भी हमेशा ऐसा ही किया जाता रहेगा। इसके संदर्भ में यह भी मानना अनुचित नहीं होगा कि गरीबी शब्द ही मजदूर दिवस जैसे शब्द का सूत्रक है। और अगर गरीबी नहीं होती तो शायद मजदूर दिवस मनाया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक हिसाबसे हम सभी मजदूर ही हैं बस अंतर इतना है। कोई अमीर मजदूर है तो कोई गरीब मजदूर है। -- और इन्हीं अमीर मजदूरों से ज्यादा है गरीब मजदूर।

यह मई दिवस उन्हें गरीब मजदूरों का है। और यह हमेशा यूँ ही मनाया जाता रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि गरीब मजदूरों की संख्या अमीर मजदूरों से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ अमीर मजदूर का मतलब उन सभी से है जो गरीब मजदूरों की तरह आज भी भूखे पेट नहीं सोते। जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। जिन्हें आज भी अपनी बेटियों की शादी करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। गंभीर बीमारियों के इलाज के अभाव में पैसे की वजह से जो आज भी दम तोड़ देते हैं। ईद पत्थर छोड़े बगैर, रिश्ता चलाए बगैर, बोझ उठाये बगैर और फावड़ा या हल चलाए बगैर भूखे पेट सोने या नो बदन रहने को मजबूत होते हैं। संक्षेप में यह भी कहा जा सकता है कि, जिनके सपने रहते हमेशा चूर-चूर हैं, वो

और कोई नहीं साहब, लोगों के शोक पूरे करने वाला एक मजदूर है। जैसा कि सर्व विदित है कि इन मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों के नाम समर्पित यह दिन 1 मई है। मजदूर दिवस को 'लेबर डे', श्रमिक दिवस या मई डे' के नाम से भी जाना जाता है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से भी इस दिन गौरव, रिश्ता चलाए बगैर, बोझ उठाये बगैर और फावड़ा या हल चलाए बगैर भूखे पेट सोने या नो बदन रहने को मजबूत होते हैं। देश के विकास के लिए अहम भूमिका में होते हैं। हर कार्य क्षेत्र मजदूरों के परिश्रम पर निर्भर करता है। मजदूर किसी भी क्षेत्र



विशेष को बढ़ावा देने के लिए श्रम करते हैं। हर बार मजदूर दिवस को एक थीम होती है, जिसके आधार पर इन दिनों को मनाया जाता है। इस वर्ष मजदूर दिवस 2024 की थीम

'जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।' लेकिन यहाँ कितना हो पाएगा या सब कुछ करने वालों की मंशा पर ही निर्भर करता है। अवाग्न करारते चले कि पहली बार मजदूर दिवस 1889 में मनाया का फैसला लिया गया। इस दिन को मनाया की रूपरेखा अमेरिका के शिकागो शहर से बनने लगी थी, जब मजदूर एक होकर सड़क पर उतर आए थे। 1886 से पहले अमेरिका में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर सड़कों पर आए। अपने हक के लिए मजदूर हड़ताल पर बैठ गए। इस आंदोलन का कारण

मजदूरों की कार्य अवधि थी। उस दौरान मजदूर एक दिन में 15-15 घंटे काम करते थे। आंदोलन के दौरान मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी। इस दौरान कई मजदूरों की जान चली गई। सैकड़ों श्रमिक घायल हो गए। इस घटना के तीन साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि हर मजदूर से प्रतिदिन 8 घंटे ही काम लिया जाए। वहीं सम्मेलन के बाद 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस दिन हर साल मजदूरों को छुट्टी देने का भी फैसला लिया गया। बाद में अमेरिका के मजदूरों की तरह अन्य कई देशों में भी 8 घंटे काम करने के नियम को लागू कर दिया गया। अमेरिका में मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव 1 मई 1889 को

लागू हुआ, लेकिन भारत में इस दिन को मनाने की शुरुआत लगभग 34 साल बाद हुई। भारत में भी मजदूर अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मजदूरों का नेतृत्व वामपंथी कर रहे थे। उनके आंदोलन को देखते हुए 1 मई 1923 में पहली बार चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई। कई संगठन और सोशल पार्टी ने इस फैसले का समर्थन किया। लेकिन आज के परिवेश में मजदूर दिवस मनाना न एक तरह से खाना पूरी जैसा है, क्योंकि मजदूर की वास्तविक परिभाषा में आने वाला व्यक्ति आज भी अपनी समस्याओं को लेकर हताश निराश और परेशान है।

“सीमा पार क्रैद एक सिपाही: गर्भवती पत्नी की पुकार और हमारी चुप्पी”

“पूर्वम को लौटाओ: एक अजन्मे बच्चे की पहली माँग”
“देश चुप है, पत्नी नहीं: एक सिपाही की वापसी की जंग”

बीएसएफ के जवान पूर्वम साहू पिछले एक सप्ताह से पाकिस्तान के कब्जे में हैं। वह ड्यूटी के दौरान सीमा पार कर गए और तबसे कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाया है। उनकी पत्नी आठ महीने की गर्भवती हैं और अपने पति की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। यह सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं, बल्कि एक अजन्मे बच्चे के पिता को वापस लाने की जद्दोजहद है। यह समय है जब हम सबको मिलकर एक आवाज बनना चाहिए, ताकि उनकी रिहाई सुनिश्चित की जा सके और यह संघर्ष अकेला न रह जाए।

—प्रियंका सौरभ

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान पूर्वम साहू पिछले एक सप्ताह से पाकिस्तान के कब्जे में हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक त्रासदी है, जिसमें एक गर्भवती पत्नी की रातें करवटों में बीत रही हैं, एक माँ बनने वाली स्त्री अपने अजन्मे बच्चे के पहले हीरो को वापस लाने के लिए लड़ रही है।

यह कहानी न तो किसी फिल्म की पटकथा है, न ही किसी काल्पनिक उपन्यास की घटना। यह आज के भारत की सच्चाई है, और सवाल यह है — क्या हम सब अब भी चुप रहेंगे? पूर्वम साहू, छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले एक बहादुर बीएसएफ जवान हैं। ड्यूटी के दौरान वह गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान की सीमा में चले गए, जहाँ उन्हें पकड़ लिया गया। ऐसी घटनाएँ अतीत में भी हुई हैं, लेकिन इस बार जो बात इसे और संवेदनशील बनाती है, वह है उनकी पत्नी की स्थिति। उनकी पत्नी आठ महीने की गर्भवती हैं। एक ओर मातृत्व का इंतजार है, दूसरी ओर पतिपरायण अनिश्चितता। हर बीतता दिन उनके लिए एक सजा है। उन्हें न सिर्फ अपने बच्चे के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना है, बल्कि हर संभव दरवाजा खटखटा कर अपने पति की वापसी सुनिश्चित भी करनी है।

जब कोई अभिनेता बालों को स्टायल बदलता है, तो हजारों ट्वीट्स, मीम्स और खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। लेकिन जब एक सिपाही शत्रु देश के कब्जे में होता है, तो जनमानस की प्रतिक्रिया बेहद सीमित और धीमी क्यों होती है? क्या सैनिकों को पीड़ा अब टीवी चैनलों की टीआरपी लायक नहीं रही?

क्या देशभक्ति अब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी की धुनों तक सीमित रह गई है?

पूर्वम साहू की पत्नी की स्थिति को समझने के लिए किसी

बड़े विश्लेषण की जरूरत नहीं। कल्पना कीजिए कि आप माँ बनने वाले हैं, और उसी वक्त आपका जीवनसाथी एक शत्रु देश के कैदी के रूप में कहीं बंद है। न कोई सूचना, न कोई बातचीत, बस इंतजार और आँसू।

वह रोज अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। वह अपील कर रही हैं प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक, लेकिन उनकी गुहार मीडिया की हेडलाइन नहीं बन रही।

एक सवाल बार-बार उठता है — क्या अगर यही स्थिति किसी मंत्री या अमीर उद्योगपति के परिवार के साथ होती, तो भी प्रतिक्रिया इतनी धीमी होती?

सरकारों का पहला कर्तव्य होता है अपने नागरिकों और विशेषकर अपने सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध चाहे जैसे भी हों, लेकिन मानवीय आधार पर सैनिकों की वापसी के लिए निरंतर बातचीत और दबाव बनाना सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है।

बीते वर्षों में हमने देखा है कि कई बार पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को रगलती से सीमा पार करने के बाद लौटाया है। ऐसे में सरकार की ओर से तत्काल कदम उठाना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाना और राजनयिक चैनलों से संपर्क बनाए रखना आवश्यक है।

लेकिन क्या आज वैसा कुछ होता दिख रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं। आज के दौर में एक हैशटैग, एक वायरल पोस्ट, एक जन अभियान — सरकारों को झकझोरने की ताकत रखता है। हमें पूर्वम साहू की पत्नी के संघर्ष को उनका अकेला युद्ध नहीं बनने देना चाहिए। आप ये कर सकते हैं:

1. सोशल मीडिया पर #BringBackPurnamSahu ट्रेंड करवाइए।
 2. अपने क्षेत्रीय सांसद और विधायकों को मेल और पत्र लिखिए।
 3. ऑनलाइन याचिका (Petition) पर हस्ताक्षर करिए और उसे साझा करिए।
 4. मीडिया चैनलों को मेल कर इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध कीजिए।
 5. स्थानीय स्तर पर कैंडल मार्च, जनसभा या शांति प्रदर्शन आयोजित कीजिए।
- पूर्वम साहू की पत्नी की लड़ाई, हर उस स्त्री की लड़ाई है जो सीमाओं पर देश की रक्षा में लगे पुरुषों के इंतजार में जीवन काटती है। यह हर उस परिवार की कहानी है जो 'सरहद के इस पार' रोज-रोज डर के साथ जीते हैं। उनकी पत्नी की आँखें सवाल कर रही हैं —
“क्या मेरा बच्चा अपने पिता को देख भी पाएगा?”
“क्या उसकी पहली तस्वीर अस्पताल की दीवार पर नहीं,



अखबार के कॉलम में होगी?”

“क्या वाकई मेरे पति की वर्दी उनके जीवन की गारंटी नहीं है?”
जिस मीडिया को एक मंत्री के छींकने तक की खबर रेकॉर्डिंग लगती है, वही मीडिया पूर्वम साहू की खबर को 30 सेकंड की फुटेज से आगे क्यों नहीं ले जा रहा?

क्या आज देश के सैनिकों की कहानियाँ न्यूज़वर्ल्ड नहीं रह गईं?

क्या सैनिकों के लिए हमारी संवेदनाएँ अब 'रीटवीट' तक सिमट कर रह गई हैं?

पूर्वम साहू आज एक देश के हाथों बंधक नहीं, हमारी उदासीनता के हाथों बंधक हैं। उनकी पत्नी अकेली नहीं रो रही, देश की आत्मा भी रो रही है — सिर्फ हम उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे।

हर बार जब हम चुप रहते हैं, एक सैनिक की उम्मीद मरती है।

हर बार जब हम बेपरवाह रहते हैं, एक बच्चे का भविष्य अंधेरे में चला जाता है।

आज जरूरत है कि हम मिलकर एक स्वर बनें — पूर्वम साहू की पत्नी की पुकार को इतना बुलंद करें कि वो भारत की संसद तक गुंजे।

उनके अजन्मे बच्चे को हम सबका प्रेम मिले, और उसका जन्म एक उम्मीद बन जाए, न कि एक त्रासदी।

एक पोस्ट करें, एक अपील करें, एक आवाज बनें।

क्योंकि जब एक सैनिक सीमा पर हमारे लिए खड़ा रहता है, तो उसकी पीठ पर हमारी चुप्पी नहीं, हमारी समर्थन की गरज होनी चाहिए।

जाति जनगणना का फैसला स्वागत योग्य: समाजवादी पार्टी



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूवनेश्वर : भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा 2026 में आगामी जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दिए जाने के बाद पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय का द्वार खुल गया है। समाजवादी पार्टी ओडिशा राज्य कमेटी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव

हाथी यादव ने प्रेस विज्ञापित जारी कर कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की लम्बे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करने के लिए वह सरकार की सराहना करते हैं।

उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराने से न केवल समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास और उत्थान में मदद मिलेगी, बल्कि सरकार को दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाने में भी मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार के फैसले के बाद पार्टी ने मांग की है कि ओडिशा सरकार मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू करें, पंचायत राज व्यवस्था में पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दे और एसईबीसी को दरकिनारा कर मध्यम वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करें।

चारधाम यात्रा शुरुआत अक्षय तृतीया से होती...!



संजय एम तराणेकर

चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है, गंगोत्री और यमुनोत्रीधाम के कपाट खुलने से होती है। गंगोत्री को माता गंगा का उदगम स्थल माना जाता है। यमुनोत्री में यमुनामाता अवतरित हुईं ये कहा जाता है। गर्मियों में गंगा-यमुना-अपने-अपने निवास विराजमान, सर्दियों में मुखबा-खरसाली गांव में स्थापित देते मान।

चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है, गंगोत्री और यमुनोत्रीधाम के कपाट खुलने से होती है। उनकी विग्रह मूर्त को शीतकालीन प्रवास कराते हैं,

गंगोत्री मायके से खास चीज सहित विदा हो जाती हैं। पौराणिक मान्यता है भीमरथ ने कठोर तपस्या की थी, तब जिसके फलस्वरूप गंगा धरती पे अवतरित हुई थीं।

चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है, गंगोत्री और यमुनोत्रीधाम के कपाट खुलने से होती है। भीमरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगा को बुलाया, गंगा का प्रवाह ज्यादा था शिवजी ने जटाओं में समाया। भीमरथी नदी पर एक चट्टान पे यह शिवलिंग स्थित है। सर्दियों में जलस्तर कम हो शिवलिंग दिखे व्यवस्थित है।